वर्ष : 34 | अंक : 350 | मुंबई, गुरुवार, 26 फरवरी 2026 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

बजट आकार में 19.35 प्रतिशत की वृद्धि

वर्तमान वर्ष का संशोधित बजट 67,515 .40 करोड़ रुपये रहा, जबकि आगामी वर्ष का बजट 19 .35 प्रतिशत बढ़कर 80,952 .56 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 48,164 .28 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। यह राशि 2025-26 के मुकाबले 11 .59 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व व्यय 32,698 .44 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जो 2025-26 के 28,257 .91 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से लगभग 15 .71 प्रतिशत अधिक है। बजट में अनुमानित राजस्व आय 51,510 .94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। जो सालाना आधार पर 19 .35 प्रतिशत अधिक है। संपत्ति कर राजस्व, जो बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में एक है, 2026-27 के लिए 7,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2025-26 में 6,200 करोड़ रुपये था।

किस मद में कितना आवंटन

खबर के मुताबिक, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत (48,164 .28 करोड़ रुपये) कैपिटल खर्च के लिए आवंटित किया गया है। यह हिस्सा मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं और दीर्घकालिक निवेश पर केंद्रित होगा। वहीं, बाकी 40 प्रतिशत (32,788 .28 करोड़ रुपये) रेवेन्यू खर्च के लिए रखा गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, मेंटेनेंस और विभिन्न नागरिक सेवाओं के संचालन की लागत शामिल है।

राजस्व वृद्धि के प्रमुख स्रोत

राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क मुआवजे से 15,550 .02 करोड़ रुपये, विकास योजना विभाग से 12,050 करोड़ रुपये और संपत्ति कर से 7,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा निवेश पर ब्याज से 2,572 .23 करोड़ रुपये, जल व सीवेज कर से 3,578 .26 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन, लाइसेंसिंग और सरकारी बकाया से भी आय का अनुमान है।

80,952 करोड़ का बजट पेश

धीरज सिंह । मुंबई

देश की सबसे अमीर महानगरपालिका मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने स्थायी समिति के समक्ष 80,952.56 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल के 74,427 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इस बार 8.77 प्रतिशत (6525 करोड़) की बढ़ोतरी की गई है। चार साल बाद यह निर्वाचित प्रतिनिधियों और नई सत्ता की मौजूदगी में पेश किया गया पहला बीएमसी बजट है।

36 हजार करोड़ की FD का होगा इस्तेमाल

इस बजट की सबसे बड़ी चर्चा बीएमसी के पास जमा सावधि जमा (Fixed Deposits) को लेकर है। वर्तमान में बीएमसी के पास कुल 81,449 .32 करोड़ रुपये की एफडी जमा है। बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें से 36,623 .09 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निकाली जाएगी। शेष लगभग 44,826 करोड़ रुपये की एफडी विभिन्न बाध्यताओं के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। विपक्षी दलों, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) द्वारा पहले ही यह आरोप लगाया जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन के बाद मुंबई की जमा पूंजी यानी एफडी का उपयोग भाजपा सरकार करेगी। अब बजट में इस बड़े फंड के इस्तेमाल की आधिकारिक घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना है। बीएमसी प्रशासन का तर्क है कि बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए एफडी की रकम का उपयोग जरूरी है।

- 80,952 करोड़ रुपये का बजट बीएमसी ने किया पेश
- विकास कार्यों के लिए 48,164 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।
- इतिहास में पहली बार विकास के लिए तोड़ी जाएगी 36,000 करोड़ रुपये की एफडी
- पिछले वर्ष के 74,427 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में इस बार 6,525 करोड़ रु. की वृद्धि हुई
- 10948.58 करोड़ रुपये राज्य सरकार पर कुल बकाया

बीएमसी की कमाई के मुख्य सोर्स

- ऑक्ट्रॉई के बदले मुआवज़ा – RS 15,550.02 करोड़
- डेवलपमेंट प्लान (DP) फीस और प्रीमियम – RS 12,050.00 करोड़
- प्रॉपर्टी टैक्स – RS 7,000 करोड़
- इन्वेस्टमेंट पर ब्याज – RS 2,572.23 करोड़

बजट को एक रणनीतिक ढांचे के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और आधुनिक व समावेशी मुंबई के विकास-विजन के बीच संतुलन कायम करना है। इसमें राजस्व आय का अनुमान 51,510 .94 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 .35 प्रतिशत अधिक है। स्टांप ड्यूटी रेडी रेकनर तथा विकास योजना शुल्क व प्रीमियम के आधार पर संशोधित कैपिटल वैल्यू लागू होने के बाद संपत्ति कर से 7,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे नगर निगम को कुल 12,050 करोड़ रुपये का योगदान मिलने की उम्मीद है। वहीं, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भारी आवंटन किया गया है।

-भूषण गगरानी, बीएमसी कमिश्नर

बजट अनुमान की प्रमुख बातें (संक्षेप में):

- 40 स्कूलों में एस्ट्रोनॉमिकल लैब की स्थापना, इसके लिए 3 करोड़ रुपये (प्राइमरी) का प्रावधान।
- नगर निगम की 2 स्कूल इमारतों में प्रयोगात्मक रूप से साइंस पार्क विकसित किए जाएंगे, इसके लिए 5 करोड़ रुपये तय।
- नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के माध्यम से कक्षा 8 और 9 के छात्रों को साइबर लिटरेसी ट्रेनिंग, इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी विभाग को 11.80-11.80 करोड़ रुपये।
- स्कूलों की लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नगर निगम स्कूलों के लिए म्यूजिक मटीरियल की खरीद, इसके लिए 1.35 करोड़ रुपये।
- छात्रों को आर्ट और वर्क एक्सपीरियंस किट देने की योजना, इसके लिए 5.25 करोड़ रुपये।

कौन-कौन रहा मौजूद?

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भूषण गगरानी ने बजट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे को पेश किए। इस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के साथ एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ विपिन शर्मा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) डॉ (मिसेज) अश्विनी जोशी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (ईस्टर्न सबर्ब्स) डॉ अविनाश ढकने, डिप्टी कमिश्नर (फाइनेंस) प्रशांत गायकवाड़, म्युनिसिपल सेक्रेटरी मंजरी देशपांडे और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

कर वृद्धि से राहत, मनोरंजन शुल्क की वापसी का प्रस्ताव

- बजट में मुंबईवासियों पर किसी भी प्रकार के नए कर, शुल्क या मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष 2017 से बंद मनोरंजन शुल्क को फिर से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

फेरीवालों को मिलेगा क्यूआर कोड प्रमाणपत्र

- नगर आयुक्त ने घोषणा की कि शहर के फेरीवालों को पहचान और पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिससे व्यवस्था और निगरानी को मजबूत किया जा सकेगा।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा

- मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। मुंबई में अलग-अलग बड़े प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाने के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। एक बार में जारी किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपये के बॉन्ड के साथ केंद्र से 100 करोड़ रुपये का ग्रांट भी मिलेगा।

आंतरिक निधि और विशेष कोष से संसाधन

- अस्थायी आंतरिक हस्तांतरण के माध्यम से 13,765.74 करोड़ रुपये तथा विशेष व आरक्षित निधि से 14,294 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। बजट वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण और विशेष निधियों के आधार पर की गई है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बढ़ोतरी

- पिछले वर्ष तक स्वीकृत 2.33 लाख करोड़ रुपये की आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की राशि बढ़कर अब 2.44 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिससे शहर के विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है।

'गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस' के लिए 5 करोड़ का प्रावधान

- 'गर्ल्स अटेंडेंस अलाउंस' योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं. इस योजना के लिए प्राथमिक स्तर पर 5 करोड़ रुपये और माध्यमिक स्तर पर 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

2026-27 में मिशन SA-FAL शुरू किया जाएगा

- नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मिशन SAMPURN पहले से लागू है। अब 2026-27 में मिशन SA-FAL शुरू किया जाएगा, जिसमें शारीरिक सुदृढ़ता, स्काउट-गाइड गतिविधियां, संगीत, कला और कार्य-अनुभव आधारित कौशल विकास पर जोर रहेगा।

फायर ब्रिगेड के लिए 230.90 करोड़ रुपये दिए

- बीएमसी के 2026 के बजट में 2026-27 के बजट के तहत मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए 230.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो 2025-26 के 111.68 करोड़ रुपये के मुकाबले अनुमान से काफी ज्यादा है।

थकबाकी भुगतान की समय-सीमा तय

जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की चार माह की थकबाकी राशि मार्च 2026 के वेतन के साथ दी जाएगी। वहीं, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 की अवधि की थकबाकी के भुगतान को लेकर सरकार शीघ्र ही अलग आदेश जारी करेगी। इस निर्णय का सीधा लाभ राज्य के लगभग 5 .96 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 8 .12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। कुल मिलाकर 14 लाख से अधिक परिवारों को इस बढ़ोतरी से आर्थिक सहारा मिलेगा और बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी। सरकार की इस योजना से कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के रूप में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इससे घरेलू खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा को बल मिलेगा। फैसले की घोषणा के बाद राज्यभर की कर्मचारी यूनियनों और पेंशनधारकों ने इसका स्वागत किया है।

BEST को 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

बीएमसी ने बजट अनुमान 2026-27 के तहत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BEST अंडरटेकिंग को कुल 1,000 करोड़ रुपये दिए हैं। बीएमसी ने वर्ष 2012-13 से,लगातार BEST को सपोर्ट किया है, और जनवरी 2026 तक कुल 12,028 .81 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद दी है। इसके पीछे का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना और शहर की बस और इलेक्ट्रिक सर्विस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सपोर्ट करना है।

BEST: घर से स्कूल तक फ्री सेवा

कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को BEST बसों से घर से स्कूल तक नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। जिन मार्गों पर नियमित सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां विशेष बस सेवा चलाई जा रही है. इस योजना के लिए प्राथमिक स्तर पर 6 करोड़ रुपये और माध्यमिक स्तर पर 12 .70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन योजनाओं पर रहेगा जोर?

- मुंबई कोस्टल रोड के अगले चरणों और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) के लिए भारी आवंटन किया गया है। वर्सोवा-से-दहिसर स्ट्रेच और उसके आखिरी हिस्से (मुंबई कोस्टल रोड (नॉर्थ)) के लिए कुल मिलाकर 4,700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (GMLR) के लिए बीएमसी ने 2,650 करोड़ रुपये दिए हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे एक ट्विन टनल वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद उपनगरों के बीच यात्रा का समय 90 मिनट से घटाकर 20 मिनट करना है। सीवेज डिस्पोजल के लिए सात ट्रीटमेंट सुविधाओं के लिए 5,690 करोड़ रुपये दिए गए हैं और सीमेंट कंक्रीटीकरण के लिए नागरिक निकाय ने शहर के मेगा रोड कंक्रीटीकरण प्रोजेक्ट के फेज़-I और II के लिए 5,520.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 4,248 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7,456 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बीएमसी कमिश्नर ने बताया कि जहां तक हेल्थ और एजुकेशन की पहल का सवाल है। बीएमसी बड़े हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट पर काम कर रही है। इसमें सायन हॉस्पिटल (फेज़ I और II), एम.टी. अग्रवाल हॉस्पिटल, और भांडुप में एक नया मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल हैं। स्क्रीनिंग की सफलता पर आगे बढ़ना 2025 से 3 लाख नागरिकों को कैंसर के लिए प्रोग्राम को और मजबूत किया जाएगा। बजट कन्फर्म करता है कि भारत की जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल होगी और आबादी की गिनती फरवरी 2027 में तय है।
- मुंबई की हवा सुधारने और 'नेट जीरो' लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए 159 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है।
- देवनार में वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्लासरुम का कायाकल्प

शिक्षा समिति के लिए 4,248 .08 करोड़ की मंजूरी

महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी का बजट बुधवार (25 फरवरी) को पेश हो गया है। इस दौरान सबसे पहले शिक्षा समिति का बजट पेश हुआ। यह बजट नवनियुक्त अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने पेश किया। शिक्षा समिति के बजट के लिए बीएमसी 2026-27 के बजट में 4,248 .08 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। शिक्षा समिति को अनुमानित बजट दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3758 .08 करोड़ प्रपोज किया गया है। साल 2026-27 के कैपिटल कामों के बजट अनुमान में 490 .00 करोड़ रुपये का बजट प्रोविजन प्रपोज किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इतना है बजट

बजट 'E' फंड कोड 30 के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3544 .34 करोड़ है और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए रेवेन्यू इनकम और खर्च का बजट अनुमान 3758 .08 करोड़ प्रपोज किया गया है. साथ ही, बजट 'E' फंड कोड 30 के तहत साल 2025-26 के कैपिटल बजट में 1411.30 करोड़ रुपये का प्रोविजन प्रपोज किया गया है। रिवाइज्ड एस्टिमेट में 1386 .78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, साल 2026-27 के कैपिटल कामों के लिए बजट एस्टिमेट में 1,490 l00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रोविजन प्रस्तावित किया गया है।

साल 2026-27 में जारी रहने वाली भलाई की स्कीम

स्कूल सप्लाई की फ्री सप्लाई : साल 2026-27 और 2027-28 के लिए स्टूडेंट्स को फ्री स्कूल सप्लाई की सप्लाई के लिए टेंडर प्रोसेस डिप्टी चीफ इंजीनियर के जरिए शुरू कर दिया गया है. 150 .57 करोड़ रुपये का बजट (प्राइमरी) और 37 करोड़ रुपये का बजट (सेकेंडरी) प्रोविजन किया गया है।

मैजिक बॉक्स

क्लास I और क्लास II के सभी मीडियम की 3,083 क्लास यूनिट के लिए मैजिक बॉक्स (नॉलेज बॉक्स) दिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रोविज़न.

स्कूल बिल्डिंग की रिपेयर, अपग्रेडेशन, रिकंस्ट्रक्शन किए जाएंगे

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल 479 स्कूल इमारतों में मरम्मत, अपग्रेडेशन, रिकंस्ट्रक्शन और नए निर्माण से जुड़े 57 कार्य मार्च 2026 तक पूरे किए जाएंगे, जबकि शेष 15 कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरे होंगे, जिसके लिए प्राइमरी स्तर पर 340 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 469 स्कूल बिल्डिंग के मेंटेनेंस, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 180 .27 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सिटी डिवीजन के स्कूलों में पहले से CCTV कैमरे चालू हैं, जबकि सबअर्बन डिवीजन में CCTV लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए प्राइमरी बजट में 42 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्कूल सप्लाई की मुफ्त सुविधा के लिए प्राइमरी में 150 .57 करोड़ रुपये और सेकेंडरी में 37 करोड़ रुपये, कुल 187 .57 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट योजना हेतु प्राइमरी में 5 करोड़ रुपये और सेकेंडरी में 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि दिव्यांग छात्रों के लिए वेलफेयर स्कीम में प्राइमरी स्तर पर 25 लाख रुपये रखे गए हैं। मॉडर्न मीटिंग सिस्टम के लिए प्राइमरी में 29 .18 करोड़ रुपये और सेकेंडरी में 5 .10 करोड़ रुपये, कुल 34 .28 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। छात्रों को मुफ्त BEST बस यात्रा सुविधा देने के लिए प्राइमरी में 6 करोड़ रुपये और सेकेंडरी में 2 .70 करोड़ रुपये, कुल 8 .70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, सैनिटरी नैपकिन योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना को लगातार लागू रखा जाएगा, जिसके तहत पिछले शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कुल 1,09,810 छात्रों की मेडिकल जांच की गई थी।

साइंस लैबोरेटरी का मॉडर्नाइजेशन

साइंस लैबोरेटरी के आधुनिकीकरण के तहत कुल 190 प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें प्राइमरी स्कूलों की 90 और सेकेंडरी स्कूलों की 100 साइंस लैब शामिल हैं, जिसके लिए 10 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 19,317 टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए बजट में प्राइमरी स्तर पर 10 लाख रुपये और सेकेंडरी स्तर पर 21 .73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि विज्ञान शिक्षा को तकनीकी रूप से अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके।

ग्रांट

ग्रांट के तहत शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि स्कूलों की लाइब्रेरी सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा किंडरगार्टन कक्षाओं (प्राइमरी) के संचालन और विकास के लिए 20.33 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है।

आठ मीडियम के स्कूलों पर नजर

शहर की शैक्षणिक व्यवस्था के तहत 931 प्राइमरी स्कूलों में 2,76,115 विद्यार्थियों (1,41,013 लड़के और 1,35,102 लड़कियां) को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, जहां 7,453 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 187 सेकेंडरी स्कूलों में 34,311 छात्रों (17,292 लड़के और 17,019 लड़कियां) को नि:शुल्क शिक्षा मिल रही है और इनमें 1,177 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। विशेष बच्चों के लिए 19 स्पेशल स्कूल संचालित हैं, जिनमें 77 शिक्षक 845 विद्यार्थियों (578 लड़के और 267 लड़कियां) को शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में 118 छात्र अध्ययनरत हैं, वहीं 377 प्राइवेट एडेड स्कूलों में 2,367 शिक्षक कार्यरत हैं, जहां कक्षा 1 से 4 तक 96,513 विद्यार्थी (47,721 लड़के और 48,792 लड़कियां) पढ़ रहे हैं। शिक्षा ढांचे में 900 किंडरगार्टन क्लास, 168 एमपीएस क्लास और ICSE, IB व IGCSE बोर्ड की 115 प्री-प्राइमरी क्लास शामिल हैं, जिनमें कुल 40,595 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

डिजिटल क्लासरुम

डिजिटल क्लासरूम योजना के तहत 1,203 स्कूलों के 7,953 क्लासरूम को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जाएगा, जिसके लिए बजट में अलग-अलग स्तरों पर प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के लिए प्राइमरी स्तर पर क्रमश: 23 .38 करोड़ रुपये, 10 .50 करोड़ रुपये और 11 .50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि सेकेंडरी स्तर के लिए 1 .08 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है, ताकि शिक्षण व्यवस्था को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाया जा सके और छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो सके।

न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद की पवार अस्पताल से छुट्टी

मुंबई। शरद पवार के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें बुधवार को पुणे के रूबी क्लीनिक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। छाती में संक्रमण की शिकायत के बाद शरद पवार को 9 फरवरी को रूबी क्लीनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत में लगातार सुधार देखा गया, जिसके बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई। अस्पताल के मुख्य हृदयरोग विशेषज्ञ और प्रबंधन न्यासी डॉ. पुरवेज़ ग्रांट ने बताया कि शरद पवार अब पूरी तरह स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि पवार को अगले कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद वह धीरे-धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू कर सकेंगे। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले अस्पताल से अपने पिता को लेने पहुंचीं। उन्होंने रूबी अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का आभार जताते हुए कहा कि उनके पिता की तबीयत अब ठीक है और वह मुंबई में रहकर आराम करेंगे। सुप्रिया सुले ने बताया कि शरद पवार का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण मुंबई के ब्रीचकैंडी अस्पताल में कराया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल पवार सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहकर स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे।

अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रुपये का घर कुर्क

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सख्त कदम उठाते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में यह कदम उठाते हुए उनकी एक प्रमुख संपत्ति को कुर्क किया है।सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान आवास 'एबोड' को कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति शहर के प्रमुख इलाके में स्थित बताई जा रही है और लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, कुर्क की गई इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसे अब तक की हाई-प्रोफाइल कुर्की में से एक माना जा रहा है, जिससे मामला और भी गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है।

फलों पर लगाई चूहे मारने की दवा

मुंबई। उत्तरी उपनगर मालाड से फलों की बिक्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ विक्रेता फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर उन्हें बाजार में बेच रहे थे, जिससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान सील कर दी और दो आरोपियों को हिरासत में लिया। यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब स्थानीय नागरिक कुणाल सालुंके ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि दो फल विक्रेता चूहों से फलों को बचाने के नाम पर उन पर जहरीला पदार्थ लगा रहे थे। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। मालाड पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

10 रुपये में भरपेट खाना! शिव भोजन थाली योजना नहीं होगी बंद

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही शिव भोजन थाली योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यह आवंटन सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत किसी भी हाल में इस योजना के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

पहले भी मिल चुका है बजट समर्थन

वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार पहले ही 70 करोड़ रुपये मंजूर कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, योजना को पूरे साल सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। नए प्रावधान से योजना को मजबूती मिलेगी।

फडणवीस सरकार देगी 55 करोड़

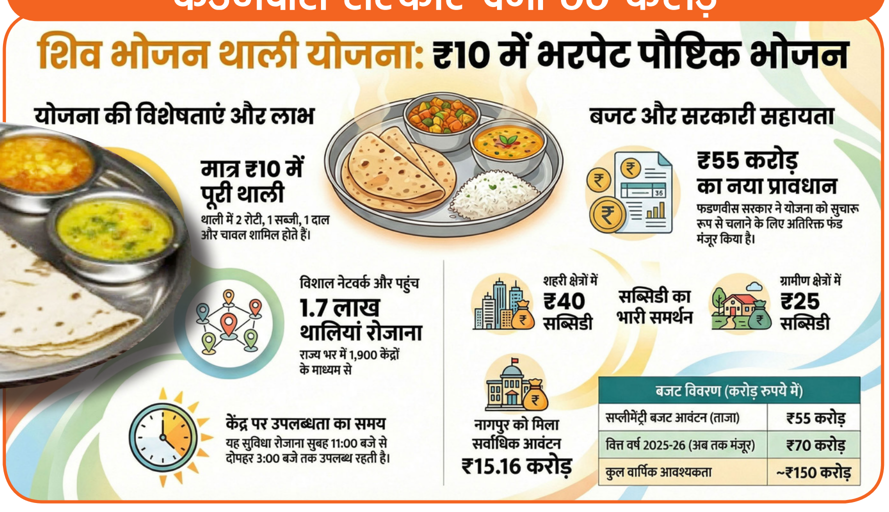

अफवाहों पर लगा विराम

बीते कुछ समय से फंड की कमी के चलते योजना के बंद होने की चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन बजट में 55 करोड़ रुपये के नए आवंटन से इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है और लाभार्थियों को राहत मिली है।

कब और कैसे शुरू हुई योजना?

शिव भोजन थाली योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2020 को तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, छात्रों और बेसहारा लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

क्या मिलता है 10 रुपये में?

इस योजना के तहत केवल 10 रुपये में थाली दी जाती है, जिसमें दो रोटी, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल और चावल शामिल होते हैं। यह भोजन रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाता है।

राज्यभर में 1,900 केंद्रों से सेवा

महाराष्ट्र में लगभग 1,900 केंद्रों के माध्यम से रोजाना 1.7 लाख से अधिक थालियां परोसी जा रही हैं। हालांकि एक थाली की वास्तविक लागत शहरों में करीब 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 रुपये है, लेकिन शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में केंद्र संचालकों को देती है।

600 से ज्यादा छात्रों का पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई यूनिवर्सिटी ने सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच 644 PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ कार्रवाई की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यह कदम नियमों के तहत उठाया गया है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों को खत्म किया जा सके और नए छात्रों के लिए सीटें खाली की जा सकें।

क्यों हुई कार्रवाई?

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों के अनुसार PhD की अवधि सामान्यत: 3 से 6 साल होती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 8 साल और महिलाओं या दिव्यांगों के लिए 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिन 644 छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, उनमें से कई 10 साल से भी ज्यादा समय से पंजीकृत थे और उनके शोध कार्य में खास प्रगति नहीं दिख रही थी। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों से सीटें ब्लॉक हो रही थीं और नए रिसर्च स्टूडेंट्स को एडमिशन में दिक्कत आ रही थी।

छात्रों का विरोध और आरोप

इस फैसले से छात्र नाराज हैं। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याओं और गाइड बदलने जैसी वजहों से उनका रिसर्च प्रभावित हुआ। एक छात्र ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद गाइड बदला गया, लेकिन अचानक रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना अन्याय है। वहीं, 52 वर्षीय बौद्ध भिक्षु और स्कॉलर भदंत विमंसा ने प्रशासन पर जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। मामला अब महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया है, जिसने यूनिवर्सिटी से 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है।

जानकारों की चिंता और राहत की घोषणा

शिक्षाविदों ने भी सवाल उठाए हैं कि इतने सालों तक मॉनिटरिंग सिस्टम ने छात्रों की प्रगति पर नजर क्यों नहीं रखी। पूर्व प्रो-वाइस चांसलर डॉ. ए.डी. सावंत का कहना है कि अगर समय रहते चेतावनी दी जाती, तो आज इतने बड़े स्तर पर छात्रों का करियर खतरे में नहीं पड़ता। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कुछ राहत भी दी है। जिन छात्रों की समय सीमा पूरी नहीं हुई है या जिन्होंने सिनोप्सिस जमा कर दिया है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक थीसिस जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है।

जेल में मिले 5 मोबाइल और 2 पावर बैंक, मामला दर्ज

डीबीडी संवाददाता | पुणे/मुंबई

येरवड़ा जेल की बैरक नंबर 1, 2 और 6 में विशेष तलाशी के दौरान 5 मोबाइल फोन और 2 पावर बैंक बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जेलकर्मी सुनील तुकाराम गायकवाड़ की शिकायत पर येरवड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

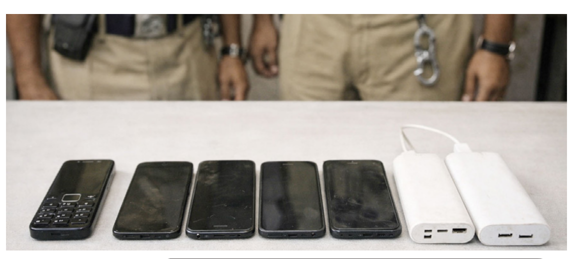

22 फरवरी को चला तलाशी अभियान

जेल उप महानिरीक्षक की अनुमति से 22 फरवरी को शाम 4 बजे से 6.30 बजे के बीच विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान बैरक नंबर 1 में बंद कैदी नौशाद शेख की बैरक के बाहर रखे बैग की जांच की गई, जिसमें बिना बैटरी का 'हीरो' कंपनी का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और चार्जिंग वायर जब्त किया गया।

मामला दर्ज, जांच जारी

इसके बाद कैदी नौशाद शेख और अन्य के खिलाफ जेल में प्रतिबंधित मोबाइल फोन व इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने का मामला दर्ज किया गया है।

बैरकों के बाहर से मिले कई मोबाइल

तलाशी के दौरान बैरक नंबर 1 के बाहर बिना बैटरी और सिम कार्ड के तीन नोकिया मोबाइल फोन पाए गए। वहीं बैरक नंबर 6 के बाहर एक मोबाइल फोन, दो पावर बैंक और एक चार्जिंग वायर भी बरामद किया गया, जिससे जेल में प्रतिबंधित सामान रखने की पुष्टि हुई।

शौचालय के पास दिखा संदिग्ध कैदी

शिकायत के अनुसार, जेल परिसर के शौचालय के पास कैदी नौशाद बदुरदीन शेख को संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। उसकी तलाशी लेने पर एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया।

बीएमसी ने घोषित किए 10 नामित पार्षद

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 10 नामित पार्षदों के नामों की घोषणा की। ये नाम एक सीलबंद लिफाफे में लाए गए थे और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार BMC द्वारा जारी किए गए। इस सूची में सबसे अधिक 4 नाम भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हैं, जबकि अन्य दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

किस पार्टी से कौन बना पार्षद

नामित पार्षदों में BJP से प्रतीक मधुसदन करपे, प्रवीण छेड़ा, नितेश सिंह और कमलाकर दलवी शामिल हैं। शिवसेना (शिंदे गुट) से राज सुर्वे और उमेश माने को नामित किया गया है। वहीं शिवसेना (UBT) की ओर से माधुरी मांजरेकर, साईंनाथ दुर्गे और कैलाश पाठक को जगह मिली है। कांग्रेस की ओर से वीरेंद्र चौधरी अकेले नामित पार्षद बने हैं।

वोटिंग अधिकार नहीं, लेकिन चर्चा में भागीदारी

इन सभी नामित पार्षदों को BMC की बैठकों में चर्चा में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। BMC में कुल 227 निर्वाचित कॉर्पोरेटर होते हैं, जो मेयर का चुनाव करते हैं। इस बार रितु तावड़े को मेयर चुना गया है, और अब नामित पार्षदों के साथ निगम की कार्यवाही में राजनीतिक संतुलन और स्पष्ट रूप से नजर आएगा।

'एसटी के डीज़ल टेंडर में दखल बर्दाश्त नहीं'

प्रताप सरनाईक की तेल कंपनियों को चेतावनी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और एसटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप सरनाईक ने तेल कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है कि एसटी के डीज़ल खरीद टेंडर में किसी भी तरह की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिडिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमित रहेगी।

डीज़ल पर भारी खर्च

एसटी को फिलहाल करीब 12,000 करोड़ रुपये का घाटा है। डीज़ल पर सालाना 3,400 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जो 8,000 नई बसें शामिल होने पर 4,700 करोड़ तक जा सकता है। मंत्री ने बताया कि यदि कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी हो जाए तो सालाना 50-55 करोड़ रुपये की बचत संभव है।

रोज़ाना डीज़ल की बड़ी खपत

राज्य की महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम को प्रतिदिन औसतन 10.87 लाख लीटर डीज़ल की आवश्यकता होती है। यह आपूर्ति मुख्यत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से होती है। होलसेल ग्राहक होने के कारण एसटी को पहले 2.70 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलती थी। हालिया बैठक के बाद इसे 30 पैसे बढ़ाया गया, जिससे सालाना 10-12 करोड़ रुपये की बचत होने लगी है।

अन्य राज्यों से कम छूट क्यों?

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशनों को 4 रुपये से अधिक, जबकि आंध्र प्रदेश में 5.50 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है। इसकी वजह वहां लागू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है। इसी तर्ज पर एमएसआरटीसी ने भी पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।

टेंडर प्रभावित करने की कोशिशें

सरकार का कहना है कि कुछ कंपनियां मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाकर प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। एक कंपनी ने कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

सरकार की प्राथमिकता

प्रताप सरनाईक ने दोहराया कि एसटी को घाटे से निकालने के लिए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है, और टेंडर प्रक्रिया में किसी भी तरह का दबाव या हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा।

प्रदूषण पर सरकार सख्त

डायनामिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने का निर्देश

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि मुंबई नगर निगम को शहर में वायु प्रदूषण के सोर्स को ट्रैक करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और एआई पर आधारित एक डायनामिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि जब तक इसका सिस्टम IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन को असरदार तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा सकेगा।

शिवसेना (यूबीटी) ने उठाया मुद्दा

प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना (UBT) एमएलसी अनिल परब ने मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी इलाके में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने पॉल्यूटेंट्स के अलग-अलग सोर्स, खासकर बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन की ओर भी इशारा किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी में गड़बड़ियों की ओर इशारा किया और कहा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर भरोसा किया जाना चाहिए।

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

सीएम फडणवीस ने कहा कि हमने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) को IoT और एआई पर आधारित एक डायनामिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा सिस्टम 100 परसेंट पॉल्यूटेंट सोर्स को ट्रैक कर सकता है, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों। उन्होंने कहा, "जब तक (सिस्टम) 100% IoT और AI-बेस्ड नहीं होगा, यह नहीं होगा। हमने ऐसे निर्देश दिए हैं और हम यह पक्का करेंगे कि यह जल्द से जल्द पूरा हो जाए।

भ्रूणहत्या के मामलों को लेकर सरकार गंभीर

राज्यभर में विशेष अभियान की घोषणा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

प्रकाश आबिटकर ने कहा कि राज्य सरकार स्त्री-भ्रूणहत्या के मामलों को लेकर गंभीर है और हर तीन महीने में प्रत्यक्ष निरीक्षण कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार (25 फरवरी) को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में उन्होंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में जांच की एक विशेष "धड़क" मुहिम चलाई जाएगी।

खबरी को इनाम और महिला अवकाश पर विचार

अवैध लिंग जांच करने वाले केंद्रों की जानकारी देने वाले खबरी को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है, जबकि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने तथा भ्रूणहत्या मामलों में मकोका लगाने के विकल्प पर कानूनी राय ली जाएगी। उन्होंने बताया कि लातूर जिले में लिंगानुपात 1265, वर्धा में 1173, धाराशिव में 1050, गडचिरोली में 1093 और गोंदिया में 1050 तक पहुंच गया है, जो सकारात्मक संकेत है।

कानून सख्त करने का संकेत

विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भ्रूणहत्या को जघन्य अपराध बताते हुए दोषी डॉक्टरों पर मकोका लगाने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक) कानून की धाराओं को और कठोर बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए विधि और न्याय विभाग से सलाह ली जाएगी।

स्टिंग ऑपरेशन और सजा के आंकड़े

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 75, वर्ष 2024-25 में 94 और जनवरी तक 90 स्टिंग ऑपरेशन किए गए हैं। इन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई की गई है। कुल 627 न्यायिक मामलों में अब तक 129 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही जनजागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है।

विधायकों ने उठाया मुद्दा

इस चर्चा में जितेंद्र आव्हाड, हेमंत ओगले, बाबासाहेब देशमुख, नमिता मुंदडा, नितिन राउत और प्रशांत बंब सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया। मंत्री ने कहा कि संबंधित जिलों में सर्वे, निगरानी और अधिकारियों के साथ समन्वय कर कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। जिला कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।

लिंगानुपात की स्थिति

मंत्री ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 913 है। लातूर, वर्धा, गडचिरोली और गोंदिया जिलों में बालिकाओं का जन्मदर पुरुषों से अधिक है, लेकिन कुछ जिलों में अब भी सुधार की आवश्यकता है। सरकार इन जिलों में विशेष निगरानी रखेगी।

बाबूओं की बल्ले बल्ले

महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी, 58 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

5.96 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 8.12 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

राज्य सरकार ने सरकारी एवं अन्य पात्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले की आधिकारिक घोषणा वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल ने विधान परिषद में एक निवेदन के माध्यम से की। मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है।

पूर्वलक्ष्यी प्रभाव से लागू होगा निर्णय

सरकार के अनुसार महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से पूर्वलक्ष्यी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से लागू की जाएगी। इससे कर्मचारियों को बीते महीनों का भी लाभ मिलेगा और उनकी आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक की चार माह की थकबाकी राशि मार्च 2026 के वेतन के साथ दी जाएगी। वहीं, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 की अवधि की थकबाकी के भुगतान को लेकर सरकार शीघ्र ही अलग आदेश जारी करेगी।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ

इस निर्णय का सीधा लाभ राज्य के लगभग 5.96 लाख कार्यरत कर्मचारियों और 8.12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। कुल मिलाकर 14 लाख से अधिक परिवारों को इस बढ़ोतरी से आर्थिक सहारा मिलेगा और बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी।

आर्थिक वर्ष के अंत में बड़ा फायदा

सरकार की इस योजना से कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के रूप में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इससे घरेलू खर्चों को संभालने में मदद मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा को बल मिलेगा। फैसले की घोषणा के बाद राज्यभर की कर्मचारी यूनियनों और पेंशनधारकों ने इसका स्वागत किया है।

पनवेल-कर्जत लाइन का 85% काम पूरा

मानसून से पहले मध्य रेलवे को मिलेगा पांचवां उपनगरीय कॉरिडोर

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मध्य रेलवे (CR) अपना पांचवां उपनगरीय कॉरिडोर प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि महत्वाकांक्षी पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल परियोजना अब पूर्णता के करीब है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 30 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तुरंत बाद ट्रेन सेवाएं शुरू होने की संभावना है।

3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) द्वारा निष्पादित इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य पनवेल और कर्जत के बीच उपनगरीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना, मौजूदा मार्गों पर दबाव कम करना और विस्तारित मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के तेजी से विकसित हो रहे नोड्स तक पहुंच को आसान बनाना है।

29.6 किमी लंबा संरेखण, पांच स्टेशन शामिल

परियोजना दस्तावेजों के अनुसार, कुल संरेखण 29.6 किलोमीटर तक फैला है और इसमें पांच स्टेशन — पनवेल, चिखले, पोयांजे (मोहपे), चौक और कर्जत — शामिल हैं। इस कॉरिडोर में दो रेल फ्लाईओवर (कुल 2.6 किमी), 47 पुल और 20 रोड ओवरब्रिज/अंडरपास बनाए गए हैं, जो इस परियोजना के विशाल इंजीनियरिंग पैमाने को दर्शाते हैं।

पहली बार बैलास्टलेस ट्रैक का उपयोग

उपनगरीय प्रणाली में पहली बार बैलास्टलेस ट्रैक (बिना गिट्टी वाले ट्रैक) का उपयोग किया गया है। MRVC के मुख्य परियोजना प्रबंधक योगेश शर्मा ने कहा,ल कि सुरंगों के भीतर बैलास्टलेस ट्रैक का काम उन्नत चरण में है और लाइनिंग तथा फिनिशिंग कार्य लगातार प्रगति पर है।

पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच निर्माण

परियोजना का संरेखण वन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ऐसे में सुरंग खुदाई और मिट्टी कार्यों के दौरान कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय अपनाए गए। अधिकारियों के अनुसार, संरचनात्मक स्थिरता और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक और उन्नत भूवैज्ञानिक मूल्यांकन का उपयोग किया गया।

यार्ड संशोधन बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती

पनवेल और कर्जत में बड़े स्तर पर यार्ड संशोधन किए गए, जिनमें जटिल पॉइंट शिफ्ट शामिल थे। यह कार्य चल रही ट्रेन सेवाओं को बाधित किए बिना किया गया, जिसे रेलवे इंजीनियरों ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि बताया है।

यात्रियों को बड़ा लाभ

परियोजना के चालू होने के बाद पनवेल और कर्जत के बीच उपनगरीय ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ेगी, यात्रा समय कम होगा और नवी मुंबई को कर्जत-कल्याण बेल्ट से जोड़ने वाला एक नया वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे भविष्य के शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

मानसून के बाद सेवा शुरू होने की संभावना

सिविल, सुरंग और ट्रैक कार्य अंतिम चरण में हैं। रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि मानसून की शुरुआत से पहले फिनिशिंग कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सुरक्षा मंजूरी और ट्रायल रन के बाद पनवेल-कर्जत कॉरिडोर पर उपनगरीय सेवाएं मानसून के तुरंत बाद शुरू होने की उम्मीद है।

मध्य रेलवे के मौजूदा कॉरिडोर

इस नए कॉरिडोर के जुड़ने के बाद मध्य रेलवे पर मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और पोर्ट लाइन के साथ यह पांचवां उपनगरीय कॉरिडोर होगा।

मुंबई उपनगरीय नेटवर्क की सबसे लंबी सुरंग

MRVC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी ने बताया कि परियोजना का एक प्रमुख आकर्षण 2.63 किलोमीटर लंबी वावरले सुरंग है, जो मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसके अलावा, संरेखण में तीन सुरंगें — नाधाल (234 मीटर), वावरले (2,639 मीटर) और किरावली (333 मीटर) — बनाई गई हैं, जिनकी संयुक्त लंबाई 3.2 किलोमीटर से अधिक है।

बारामती विमान हादसे की एफआईआर दर्ज करने से पुलिस का इनकार

शक गहराता जा रहा है: रोहित पवार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बुधवार को दावा किया कि मुंबई पुलिस ने बारामती विमान हादसे के संबंध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इनकार ने दुर्घटना के आसपास के संदेह को और गहरा कर दिया है। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई थी। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार और सरकारी

तंत्र किसी को संरक्षण देते हुए प्रतीत हो रहे थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को वीएसआर वेंचर्स के चार विमानों को उड़ान भरने से रोकने का निर्देश दिया। इस कंपनी का विमान 28 जनवरी को बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

ऑडिट टीम को मिलीं संचालन में कई खामियां

लियरजेट 45 विमान (VT-SSK) के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमानन नियामक ने वीएसआर वेंचर्स का एक विशेष सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया था। ऑडिट टीम ने विमान की उड़ान योग्यता, हवाई सुरक्षा और उड़ान संचालन के क्षेत्र में अनुमोदित प्रक्रियाओं के कई अनियमितताएं देखीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रोहित पवार ने दावा किया, 'अजीतदादा के विमान दुर्घटना के संबंध में उचित कार्रवाई की प्रतीक्षा करते हुए कल डीजीसीए की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया है कि यह दुर्घटना वीएसआर कंपनी की लापरवाही के कारण हुई थी।'

रोहित पवार का दावा- पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर

हालांकि, इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण उन्होंने पार्टी के एमएलसी अमोल मितकारी, इदरीस नाइकवाड़ी और विधायक संदीप क्षीरसागर के साथ दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जाकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि जब उनका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उनके आवेदन को केवल औपचारिकता के रूप में स्वीकार कर लिया। एनसीपी (एसपी) विधायक ने कहा, 'पुलिस के आचरण ने विमान दुर्घटना को लेकर हमारे संदेह को और भी बढ़ा दिया है। विपक्ष और सत्ताधारी दोनों दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मांग के बावजूद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने की मांग को नजरअंदाज कर रही है, तो यह महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।'

जाली आधार कार्ड के साथ 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार

वर्सोवा पुलिस की एंटी-टेरर सेल ने की कार्रवाई

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

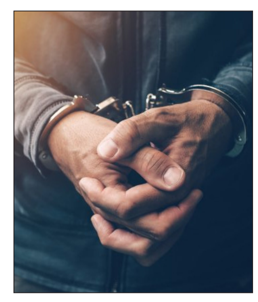

मुंबई पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग बिना वैध दस्तावेजों के पिछले कई वर्षों से रह रहे थे। पुलिस को इनके पास से बड़ी संख्या में जाली भारतीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई वर्सोवा पुलिस की एंटी-टेरर सेल द्वारा की गई।

कौन-कौन हुए गिरफ्तार?

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 21 ट्रांसजेंडर, 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। ये सभी अंधेरी पश्चिम के यारी रोड इलाके में रह रहे थे। पुलिस को लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद इस विशेष अभियान को अंजाम दिया गया। वर्सोवा पुलिस को एक मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये लोग देर रात यारी रोड पर एक दरगाह के पास इकट्ठा होने वाले हैं। इसी इनपुट के आधार पर एंटी-टेरर सेल की टीम ने योजना बनाकर इलाके में छापा मारा और सभी 25 लोगों को हिरासत में ले लिया।

जाहीर नोटीस

मैं, मोहम्मद वसीम वकील अहमद खान, निवासी रूम नं. 4, खोदावाला चॉल, नागोबा चौक, मुंबई -400022, द्वारा यह अंतिम एवं कठोर सार्वजनिक कानूनी नोटिस जारी किया जाता है।दिनांक 10/10/2025 को एग्रीमेंट क्रमांक XVFPVAS00008396343 (VFPRIME) के अंतर्गत Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. (वाशी शाखा) द्वारा लगभग ₹14,00,000/- (चौदह लाख रुपये) की राशि पर महिंद्रा थार (रजिस्ट्रेशन नं. MH27DL0003) वाहन ईएमआई आधार पर वित्तपोषित किया गया।बाद में यह ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त (Accidental) था, जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर मुझसे छिपाई गई। यह कृत्य प्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुतीकरण, आपराधिक विश्वासघात तथा उपभोक्ता को गुमराह करने की श्रेणी में आता है।इस लेन-देन में निम्नलिखित व्यक्तियों की संलिप्तता है:

अमान शेख (डीलर) - मो. 8433677041

मंगेश (वेरिफिकेशन)-मो. 9967154685

शाहनवाज उर्फ शानू (फाइल प्रोसेसिंग) - मो. 9967378786

रेहान (एजेंट) -मो. 9594577886

सलमान (रेफरेंस) - मो. 9619269137

उपरोक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 417, 418, 420 (धोखाधड़ी), धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) तथा धारा 499 एवं 500 (मानहानि) के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। साथ ही यह Consumer Protection Act, 2019 के अंतर्गत Unfair Trade Practice एवं Deficiency in Service की श्रेणी में आता है।उक्त विषय की लिखित सूचना Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. के चेन्नई स्थित मुख्य कार्यालय तथा Chunabhatti Police Station एवं Vinoba Bhave Nagar Police Station को प्रेषित की जा चुकी है।अतः इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं संस्था को अंतिम 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि प्रदान की जाती है कि वे संपूर्ण राशि वापस कर लिखित रूप में संतोषजनक समाधान प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्त होने पर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के संबंधितों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा उपभोक्ता न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में क्षतिपूर्ति दावा दायर किया जाएगा।उक्त कानूनी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी परिणाम, व्यय एवं दायित्व संबंधित पक्षों के स्वयं के होंगे। इसे अंतिम चेतावनी समझा जाए।

दिनांक: 25-02-2026
स्थळ: मुंबई

सूचना जारीकर्ता,
मोहम्मद वसीम वकील अहमद खान

पश्चिम रेलवे

ई-नीलामी सूचना - Pay & Use सामान्य शौचालय ब्लॉक अनुबंध

पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा Pay & Use Normal Toilet Blocks के संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) हेतु ई-नीलामी आमंत्रित की गई है। कैटलॉग दिनांक 23.02.2026 को IREPS वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है:
अनुबंध का प्रकार: सामान्य अनुबंध. श्रेणी: Pay & Use Toilet Blocks

ई-नीलामी कैटलॉग संख्या: MMCT-PnUT-26-09	
अनुबंध अवधि	अनुबंध अवधि
उधना रेलवे स्टेशन शौचालय ब्लॉक	3 वर्ष
विरार रेलवे स्टेशन (प्लेटफॉर्म-2, उत्तर छोर) शौचालय ब्लॉक	153 दिन
ई-नीलामी की तिथि व समय: ई-नीलामी तिथि: 10.03.2026, समय: 12:00 बजे (HRS)	

सूचना: इच्छुक बोलीदाता IREPS वेबसाइट (**www.ireps.gov.in**) के e-Auction Leasing Module में जाकर विस्तृत जानकारी देखें। लॉट-वार विवरण उक्त कैटलॉग में उपलब्ध है। शुरुआती कूलिंग ऑफ पीरियड: 30 मिनट, लगातार लॉट क्लोजिंग इंटरवल: 10 मिनट, लॉट-वार समापन समय e-auction मॉड्यूल में देखा जा सकता है। 1172

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

समग्र वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध कार्य हेतु

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (CO) द्वितीय तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई – 400008, **ई-निविदा संख्या: SG-623-1814-WA,दिनांक: 20/02/2026** आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम:** मुंबई मंडल के मुंबई सेंट्रल स्थित सेंट्रल कंट्रोल कार्यालय में स्थापित Delta निर्मित DLP आधारित रियर व्यू प्रोजेक्शन डिस्प्ले सिस्टम के लिए 03 वर्षों की अवधि हेतु समग्र वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध। **कार्य की अनुमानित लागत:** 95,57,044.20, **बोली सुरक्षा :** 1,91,200/-, **ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 16.03.2026 को 15:00 बजे तक, **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** 16.03.2026 को 15:30 बजे, निविदा विवरण देखने हेतु वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** देखें। 1161

Like us on: facebook.com/WesternRly

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि **श्री सूर्यनाथ बेनीमाधव सिंह (मृत्यु तिथि 02/12/2015) और श्रीमती दौलती सूर्यनाथ सिंह (मृत्यु तिथि 02/03/2025)** (दोनों दिवंगत), जो क्रमशः पांचवीं और सातवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या ए/504 (श्री सत्येंद्र सूर्यनाथ सिंह और श्री सूर्यनाथ बेनीमाधव सिंह द्वारा स्वामित्व) और फ्लैट संख्या बी/702 (श्रीमती दौलती सूर्यनाथ सिंह और श्री सूर्यनाथ बेनीमाधव सिंह द्वारा स्वामित्व) के स्वामी थे, ग्रीन गगन बिल्डिंग, **अकुरली श्री रिद्धि सिद्धि सीएचएसएल, अकुरली रोड, लोखंडवाला टाउनशिप, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400101** (उक्त संपत्तियां) मुंबई में स्थित हैं, के उत्तराधिकारी के रूप में, श्री सत्येंद्र सूर्यनाथ सिंह, एकमात्र पुत्र (अब 100%) ने उक्त संपत्तियों में अपने हिस्से के स्वामित्व और सदस्यता का दावा किया है और वे सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे।

उक्त संपत्तियों और दस्तावेज़ में किसी भी प्रकार के अधिकार, आपत्ति और/या दावे रखने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, सभी व्यक्तियों को एतद्द्वारा नीचे दिए गए पते पर दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित करना आवश्यक है, अन्यथा इसके बाद उनके किसी भी अधिकार, आपत्ति और/या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और वे परित्याग या त्याग दिए जाएंगे। सोसायटी उक्त संपत्तियों के संबंध में मृतक सदस्य के शेयरों और हितों को सोसायटी के उपनियमों के अनुसार हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अकुरली श्री रिद्धि सिद्धि सीएचएसएल के लिए
हस्ताक्षर/- माननीय सचिव
डी/002, ग्रीन गगन, लोखंडवाला टाउनशिप,
अकुरली रोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400101

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ई-निविदा सूचना

विभाग	सहायक अभियंता (कार्य) 'ए' विभाग
विषय	'ए' विभाग के दुर्गम क्षेत्रों में समुद्र किनारे स्थित कचरे को उठाकर ले जाने हेतु निजी ठेकेदार की नियुक्ति के संबंध में।
बोली प्रारंभ दिनांक व समय:	26.02.2026 सुबह 11:00 बजे से
बोली समाप्ति दिनांक व समय:	04.03.2026 सुबह 11:00 बजे तक
वेबसाइट:	http://mahatenders.gov.in
संबंधित अधिकारी व दूरभाष क्रमांक:	अरुण एस वैद्य ए.ई. (एसडबल्यूएम) ए वार्ड ऑफिस दूरभाष: 22661352 मोबाइल: 9820739100
ई-मेल:	aeswm.a@mcgm.gov.in

हस्ता/-
सहायक आयुक्त,
'ए' विभाग

पीआरओ./3106 /विज्ञा./2025-26

हल्का बुखार होने पर डॉक्टर से मिलें।

पश्चिम रेलवे

परामर्श सेवाओं के लिए निविदा सूचना

ACM (G) - BCT, निविदा संख्या: WRM-MCTNFRCONSULTOOH2 आमंत्रित करते हैं। **कार्य का नाम:** चर्चगेट से विरार के बीच आउट ऑफ होम (OOH) एसेट्स (होर्डिंग्स, गैन्ट्री, यूनिपोल) की पहचान, मूल्यांकन एवं टेंडर पैकेजिंग हेतु परामर्श सेवाओं की नियुक्ति। **विज्ञापित मूल्य:** 9,95,000/-, **जमानत राशि (EMD):** 19,900/-, **निविदा दस्तावेज शुल्क:** 5,000/-, **बोली प्रारंभ तिथि:** 04.03.2026, **निविदा समापन तिथि एवं समय:** 18.03.2026 को 15:00 बजे तक, **संपर्क विवरण: लैंडलाइन नंबर:** 022-67644212, **ईमेल:** acmadvtgbct@gmail.com, **कार्य समय:** प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक, **कार्यालय का पता:** वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. Divisional Commercial Manager) DRM कार्यालय, एनेक्स बिल्डिंग, प्रथम तल, वाणिज्य विभाग, NFR सेक्शन, मुंबई सेंट्रल – 400008. अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.ireps.gov.in देखें। 1157

Like us on: facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

ओएचई संशोधन कार्य

खुली ई-निविदा संख्या: केवायएन-एलडी-585 डब्लु - 771- कांट, दि. 23.02.2026. कार्य का विवरण: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के शेलू स्टेशन के पीएफ-1 और 2 के विस्तार के संबंध में मौजूदा ओएचई में परिवर्तन। **अनुमानित लागत:** रु.40,91,976.97. **ईएमडी:** रु. 81,800/-. **निविदा पपत्र का शुल्क:** रु.0/-. **समापन अवधी:** 6 महिने। **ई- निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं अवधि दि. 17.03.2026 को 11:00 बजे है।** ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा की जानकरी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क. वि.) मध्य रेल, कल्याण के सुचना पट पर उपलब्ध है। AK-930

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग यूनिट-हीट एक्सचेंजर

उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (स.मा.वि .) सवारी व मालडिब्बा कारखाना, माटुंगा, मुंबई - 400019. **निविदा सूचना क्र.: CWE /MTN/85265236 /2026 due on 30-Mar-2026. निविदा विवरण:** सीमेंस कंपनी के GP194 मॉडल के ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त हिंज युक्त ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग यूनिट-हीट एक्सचेंजर, जो मेसर्स सीमेंस पार्ट नंबर N311886-17 FO 01 या मेसर्स AKG ड्राइंग नंबर 0198.078.0000 के अनुसार है। सामग्री केवल OEM या उनके अधिकृत वितरकों से ही निविदा विशिष्ट प्राधिकरण पत्र के साथ प्राप्त की जानी चाहिए। मात्रा वितरण - MTN EMU - 09 नग और Kalva कार शेड EMU 09. मात्रा वितरण के अनुसार माल प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाना है। **मात्रा:** 18 Nos. **नियत तारीख:** 30-Mar-2026. **राशि:** 23362092. AK-935

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

मुंबई स्लम सुधार बोर्ड

(महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक क्षेत्रीय इकाई)

म्हाडा MHADA

दूरभाष क्रमांक 022-66405250, ई-मेल - eee.east1@gmail.com

क्रमांक: EE/East/MSIB/e-tender/Labour Soc/66/2025-26

कार्यकारी अभियंता (पूर्व) प्रभाग, मुंबई स्लम सुधार बोर्ड (MHADA की इकाई), कक्ष क्रमांक 536, चौथा तल, गृहनिर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 फोनः (022) 66405251 द्वारा DDR, पूर्व उपनगर, मुंबई में पंजीकृत श्रमिक सहकारी संस्थाओं (Labour Co-op. Societies) से B-1 (प्रतिशत दर) पद्धति में कुल 07 कार्यों हेतु ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज महाराष्ट्र शासन के पोर्टल https://mahatenders.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज अपलोड भी इसी वेबसाइट पर किए जाएंगे। निविदा दस्तावेज बिक्री अवधिः प्रारंभ तिथिः 27/02/2026, समय 03:05 बजे अपराह्न, समापन तिथिः 06/03/2026, समय 06:15 बजे सायं, अन्य शर्तेंः यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र (Corrigendum/Amendment) जारी किया जाता है, तो वह केवल https://mahatenders.gov.in वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

Follow us: @mhadaofficial
CPRO/A/138

हस्ता/-
कार्यकारी अभियंता (पूर्व),
एम.एस.आई.बी. बोर्ड, मुंबई

म्हाडा-राष्ट्र का अग्रणी गृहनिर्माण प्राधिकरण

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, वाणिज्य विभाग, NFR सेक्शन,मुंबई सेंट्रल, मुंबई – 400008

कार्य: मुंबई मंडल में विभिन्न NFR मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन।

नीलामी कैटलॉग संख्या	ई-नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-PnU-25-19	16-03-2026 14:00:00

क्र. सं.	लॉट नं.	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी समाप्ति तिथि एवं समय
1	PnU-BCT-MMCT-WRL-80-25-1 (Pay & Use – लाउंज/प्रतीक्षालय/ विश्राम कक्ष/क्लोक रूम)	मुंबई सेंट्रल (MMCT) स्टेशन पर रिटायरिंग रूम/डॉरमिटरी के नवीनीकरण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ई-नीलामी	1826	16-03-26 14:30:00

नीलामी कैटलॉग संख्या:	ई-नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-81	16-03-2026 15:00:00

क्र. सं.	लॉट नं.	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की अंतिम तिथि और समय
1	ADVT-Int-S1-EMU15car-357-26-1 (Advertising – Train Interior)	मुंबई मंडल की 15 कोच वाली 10 EMU रेक्स में INSIDE PANELS एवं ROUTE MAP पर 5 वर्षों के लिए विज्ञापन प्रदर्शन	1826	16-03-26 15:30:00

संपर्क विवरण: लैंडलाइन नंबर: 022-67644212. **ईमेल आईडी: acmadvtgbct@gmail.com, नोट:** इच्छुक बोलीदाता IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) के ई-ऑक्शन लीजिंग मॉड्यूल पर विजिट करें। लॉट-वार विस्तृत जानकारी उक्त कैटलॉग के अंतर्गत उपलब्ध है। 1170

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

संपादकीय

अवैध साहूकारों पर शिकंजा

अवैध साहूकारी पर महाराष्ट्र सरकार की ताज़ा कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की परीक्षा भी है। विधानसभा में गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर का यह कहना कि महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 को और कड़ा किया जाएगा, अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि मौजूदा कानून जमीनी हकीकत से पीछे छूट गए हैं। कानून यदि कमजोर हों, निगरानी ढीली हो और पीड़ित की आवाज़ व्यवस्था तक न पहुँचे—तो साहूकारों का जाल फैलता ही है। चंद्रपुर के किसान की त्रासदी इस संकट का नग्न चेहरा है। कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने की मजबूरी केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की विफलता है जिसने उसे समय पर राहत नहीं दी। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब किसान ने मूल कर्ज से कई गुना अधिक राशि चुका दी थी, तब भी उसे अंग व्यापार के दलदल में क्यों धकेला गया? 9.15 लाख के बदले 48.53 लाख की वसूली—यह ब्याज नहीं, शोषण है। और शोषण जब अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़ जाए, तो अपराध का पैमाना स्थानीय नहीं, वैश्विक हो जाता है। सरकार द्वारा मकोका जैसे सख्त कानून लगाने पर विचार स्वागतयोग्य है, लेकिन केवल दंडात्मक कठोरता से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। अवैध साहूकारी का उन्मूलन तभी संभव है जब तीन मोर्चों पर एक साथ काम हो—कानून, प्रशासन और सामाजिक-आर्थिक विकल्प। कानून को सख्त करना जरूरी है ताकि बिना लाइसेंस कर्ज देने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके और उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। प्रशासन को सक्रिय बनाना होगा ताकि शिकायत दर्ज कराने से पहले ही जोखिमग्रस्त परिवारों की पहचान हो और उन्हें औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जाए। और सबसे अहम, किसानों तथा कमजोर वर्गों को वैकल्पिक, सुलभ और सस्ते ऋण साधन उपलब्ध कराए जाएँ। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समितियाँ बनाना एक सकारात्मक पहल है। परंतु सवाल यह है कि क्या ये समितियाँ केवल कागज़ी रिपोर्ट तक सीमित रहेंगी या सचमुच अवैध नेटवर्क की नस काटेंगी? अनुभव बताता है कि जब तक स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक अवैध साहूकार अपनी जगह बदलकर धंधा जारी रखते हैं। रिपोर्टिंग तंत्र पारदर्शी हो, शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रहे और कार्रवाई समयबद्ध हो—तभी भरोसा बनेगा। इस प्रकरण में अंग तस्करी का अंतरराष्ट्रीय आयाम चिंता को और गहरा करता है। कंबोडिया तक फैले नेटवर्क का खुलासा बताता है कि गरीबी और कर्ज का शोषण केवल आर्थिक नहीं, जैविक स्तर तक पहुँच चुका है। यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, मानवाधिकार का प्रश्न है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाना होगा ताकि ऐसे गिरोहों की जड़ पर प्रहार हो सके। अंततः, यह कहना जरूरी है कि अवैध साहूकारी पर कार्रवाई तब तक अधूरी है जब तक किसान आत्महत्या और अंग बिक्री जैसे कदम उठाने को मजबूर होते रहेंगे। नीतियाँ खेत तक उतरें, बैंकिंग प्रणाली सरल बने, सहकारी ढाँचे को पुनर्जीवित किया जाए और साहूकारों की जगह संस्थागत ऋण पहुँचे—यही स्थायी रास्ता है। चंद्रपुर का मामला चेतावनी है कि यदि आज कठोर और संवेदनशील दोनों तरह की कार्रवाई नहीं हुई, तो कल ऐसे उदाहरण बढ़ेंगे। सरकार की मंशा पर अब उसके क्रियान्वयन की कसौटी है। समाज और सत्ता—दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्ज किसी की जान का सौदा न बने।

शख्सियत — डॉ. आनंदीबाई जोशी

संघर्ष,संकल्प और अटूट इच्छाशक्ति की महागाथा

डॉ. आनंदीबाई जोशी का जीवन संघर्ष, संकल्प और अटूट इच्छाशक्ति की एक ऐसी महागाथा है, जिसने भारतीय समाज की रूढ़िवादी सोच की चूलें हिला दीं।

1865 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी यमुना (बाद में आनंदी) का जीवन उस दौर की त्रासदियों से भरा था, जहां स्त्रियों का शिक्षित होना एक अपराध माना जाता था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह अपने से 20 वर्ष बड़े गोपालराव जोशी से कर दिया गया। जीवन का सबसे निर्णायक और हृदय विदारक मोड़ तब आया, जब 14 वर्ष की आयु में आनंदीबाई ने अपने पहले बच्चे को खो दिया। चिकित्सा के अभाव में हुई उस नन्हीं जान की मृत्यु ने उनके भीतर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की, जिसने उन्हें भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं डॉक्टर बनकर उन अनगिनत माताओं और शिशुओं की जान बचाएंगी, जो सामाजिक संकोच और चिकित्सा संसाधनों की कमी के कारण असमय काल के गाल में समा जाते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं था, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध एक मूक क्रांति का शंखनाद था। आनंदीबाई का डॉक्टर बनने का स्वप्न जितना महान था, उसकी डगर उतनी ही कांटों भरी थी। उस दौर में एक हिंदू स्त्री के लिए शिक्षा प्राप्त करना और वह भी सात समुद्र पार जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना, समाज की दृष्टि में घोर पाप और धर्म भ्रष्ट करने जैसा कृत्य था। उन्हें कदम-कदम पर अपमानित किया गया, उन पर पत्थर फेंके गए और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की धमकियां दी गईं। किंतु उनके पति गोपालराव, जो स्वयं प्रगतिशील विचारों के थे, उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। 1883 में, जब आनंदीबाई ने अकेले अमेरिका जाने का साहसी निर्णय लिया, तो उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तार्किक रूप से सिद्ध किया कि भारत को हिंदू महिला डॉक्टरों की कितनी आवश्यकता है। उनके उस ओजस्वी और तर्कपूर्ण वक्तव्य ने उनके विरोधियों का मुंह बंद कर दिया और अंततः कुछ उदारवादियों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता पाई। यह उनके अटूट साहस का ही प्रमाण था कि एक साधारण युवती ने वैश्विक मंच पर अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आनंदीबाई को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। वहां की कड़ाके की ठंड, विदेशी खान-पान और शाकाहार के प्रति उनकी दृढ़ता ने उनके स्वास्थ्य को जर्जर कर दिया। उन्हें अक्सर अधपका भोजन या केवल फल खाकर गुजारा करना पड़ता था, जिसके कारण वे कुपोषण और अंततः तपेदिक (टीबी) जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गईं। शारीरिक पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उनके मानसिक बल ने उन्हें हार नहीं मानने दी। 18 मार्च 1886 को जब उन्हें 'डॉक्टर ऑफ मेडिसिन' (MD) की उपाधि प्रदान की गई, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

पहचान, राजनीति और विकास का वास्तविक प्रश्न

अमित बृज
कार्यकारी संपादक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई देशों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का प्रयास किया। भारत में बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई और कलकत्ता से कोलकाता जैसे परिवर्तन इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसी प्रकार रूस में लेनिनग्राद को सेंट पीटर्सबर्ग और स्तालिनग्राद को वोल्गोग्राद किया गया।

देश में इन दिनों शहरों, जिलों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने को लेकर व्यापक बहस चल रही है। कहीं ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का तर्क दिया जाता है, तो कहीं सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना की बात कही जाती है। कुछ लोग इसे आत्मगौरव का प्रश्न मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्रतीकात्मक राजनीति बताते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक हो जाता है कि हम ठंडे दिमाग से विचार करें कि क्या नाम बदलना वास्तव में विकास का मार्ग है, या यह केवल पहचान की राजनीति का एक रूप है। नाम किसी स्थान की पहचान मात्र नहीं होते, वे इतिहास, सत्ता और सामाजिक स्मृति के वाहक भी होते हैं। औपनिवेशिक काल में अनेक शहरों और क्षेत्रों के नाम विदेशी शासकों की सुविधा या उनके प्रभाव के अनुरूप रखे गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई देशों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने का प्रयास किया। भारत में बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई और कलकत्ता से कोलकाता जैसे परिवर्तन इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। इसी प्रकार रूस में लेनिनग्राद को सेंट पीटर्सबर्ग और स्तालिनग्राद को वोल्गोग्राद किया गया। अफ्रीकी देशों में भी औपनिवेशिक शासकों के नाम हटाकर स्थानीय भाषाओं और नायकों को सम्मान दिया गया। स्पष्ट है कि नाम परिवर्तन कोई नई या अकेली घटना नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर यह समय-समय पर होता रहा है। फिर भी मूल प्रश्न यही है कि क्या नाम बदलने से आम नागरिक का जीवन बेहतर होता है? विकास का अर्थ है बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित परिवेश, रोजगार के अवसर और सामाजिक न्याय।

यदि किसी शहर का नाम बदल दिया जाए, पर वहां की सड़कें टूटी रहें, पेयजल की समस्या बनी रहे और युवाओं को रोजगार न मिले, तो नाम परिवर्तन जनता के जीवन में ठोस बदलाव नहीं ला सकता। विकास नीतियों, संसाधनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से आता है, न कि केवल प्रतीकात्मक निर्णयों से। इसलिए यह मान लेना कि नाम बदलते ही समाज प्रगति कर लेगा, यथार्थ से दूर दृष्टिकोण होगा। हालांकि यह भी सच है कि नाम परिवर्तन का एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब किसी समाज को लगता है कि उसके इतिहास और परंपराओं को उचित सम्मान नहीं मिला, तब नाम बदलना आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का माध्यम बन सकता है। स्थानीय भाषा में नाम होने से लोगों में अपनत्व की भावना बढ़ती है। नई पीढ़ी अपने इतिहास को जानने के लिए प्रेरित होती है। कई बार यह कदम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक भी बनता है।

अतः इसे पूरी तरह निरर्थक या व्यर्थ कहना भी न्यायसंगत नहीं होगा। समस्या तब उत्पन्न होती है जब नाम परिवर्तन विकास के वास्तविक प्रश्नों पर पर्दा डालने का साधन बन जाए। यदि जनता की बुनियादी समस्याएं जस की तस रहें और केवल नाम बदलने की घोषणाएं होती रहें, तो यह असंतोष को जन्म दे सकता है। प्रशासनिक स्तर पर भी नाम परिवर्तन सरल प्रक्रिया नहीं है। सरकारी दस्तावेज, अभिलेख, संकेतक, मानचित्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र और विभिन्न पंजीकरणों में बदलाव करना पड़ता है, जिसमें समय और धन दोनों का व्यय होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि नागरिक यह प्रश्न उठाएं कि क्या यही संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर खर्च नहीं किए जा सकते थे। विश्व स्तर पर देखें तो अनेक देशों में राज्यों, प्रांतों और शहरों के नाम बदले गए हैं।

एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन, स्वतंत्रता आंदोलन या शासन परिवर्तन के बाद यह प्रक्रिया देखी गई है। परंतु जिन देशों ने वास्तविक प्रगति की, वहां नाम परिवर्तन के साथ-साथ संस्थागत सुधार, आर्थिक नीतियां और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी समान रूप से लागू किए गए। केवल नाम बदलने से किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई, बल्कि शिक्षा, उद्योग, प्रौद्योगिकी और सुशासन ने विकास को गति दी। अंततः निष्कर्ष यही है कि नाम परिवर्तन एक सांस्कृतिक या राजनीतिक कदम हो सकता है, पर इसे विकास का पर्याय नहीं माना जा सकता। यदि यह कदम व्यापक सामाजिक सुधारों के साथ जुड़ा हो, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हमारी गीता

कौरवों का शिष्टाचार बनाम पांडवों का प्रेम

स्वामिनी निष्कलानंदा
चिन्मय मिशन कल्याण

महाभारत के युद्ध का प्रारंभ केवल सेनाओं का मिलन नहीं, बल्कि दो भिन्न जीवन-दर्शनों का टकराव था। कौरवों की सेना ऊपर से अत्यंत अनुशासित और शिष्टाचार (Protocol) से बंधी दिखाई देती है। नियम के अनुसार, कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म ने पहला शंखनाद किया और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से अन्य योद्धाओं ने शंख बजाए। यह एक 'टीप-टॉप' व्यवस्था थी, जो बाहर से आदर्श किंतु भीतर से खोखली थी। इसके विपरीत, पांडवों के पक्ष में यह अनुशासनहीनता लग सकती है कि सेनापति धृष्टद्युम्न के बजाय सारथी बने श्रीकृष्ण ने पहला शंख बजाया। नियम और प्रोटोकॉल के स्थान पर वहाँ प्रेम और समर्पण की प्रधानता थी। पांडवों के लिए श्रीकृष्ण केवल सारथी नहीं, बल्कि उनके सर्वेसर्वा थे। जहाँ गहरा प्रेम और ऐक्य भाव होता है, वहाँ 'पहला' या 'दूसरा' होने की औपचारिकताएँ गौण हो जाती हैं। पांडवों का सैन्य भावबद्ध और आत्मबद्ध था, जहाँ रिश्तों की अटूट डोर नियमों से बड़ी थी। कौरवों के शिष्टाचार के पीछे अहंकार और वैरभाव छिपा था। जब तक भीष्म

लड़े, द्रोण शांत रहे; द्रोण के रहते कर्ण नहीं आया। यह अनुशासन नहीं, बल्कि आपसी ईर्ष्या और स्वार्थ का प्रतीक था। इसके विपरीत, पांडवों में एकता और निस्वार्थ सेवा का भाव था। जैसे एक सुखी परिवार में दादाजी स्वयं पीछे रहकर पोते को आगे करते हैं, वैसे ही पांडवों के यहाँ शिष्टाचार से अधिक आत्मिकता थी। आज के समाज और परिवारों का चित्र भी कुछ ऐसा ही है। कई परिवार बाहर से शिष्टाचार का पालन करते दिखते हैं, परंतु उनके भीतर प्रेम का अभाव होता है। हमें अर्जुन बनने के लिए केवल साहस नहीं, बल्कि वह पांडव-भाव चाहिए जहाँ समर्पण और बंधुभाव ही सबसे बड़ा अनुशासन हो। अंततः, शिष्टाचार समाज को चला सकता है, लेकिन केवल निस्वार्थ प्रेम और एकता ही जीवन को विजयी बना सकती है।

जीवन ऊर्जा

विक्टर ह्यूगो : जन्म - 26 फरवरी 1802 — जन्म

विचारों की वह आवाज जिसे समय रोक न सका

महान फ्रांसीसी साहित्यकार विक्टर ह्यूगो का जन्म 26 फरवरी 1802 को फ्रांस के बेसाकोन में हुआ था। उनकी मृत्यु 22 मई 1885 को पेरिस, फ्रांस में 83 वर्ष की आयु में हुई थी। उनके निधन पर पूरे फ्रांस में शोक मनाया गया था और उनके अंतिम संस्कार में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए थे, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

जीवन का सबसे बड़ा सुख यह विश्वास है कि हमें प्यार किया जाता है। जहां प्यार की कमी है, वहां जीवन का कोई अर्थ नहीं है। प्रेम वह एकमात्र चीज है जो हृदय को बड़ा बनाती है। नरक का दूसरा नाम अकेलेपन में प्यार की कमी है। दूसरों को क्षमा करना प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। प्यार एक फूल की तरह है, जिसे खिलने के लिए दया की धूप चाहिए। किसी को प्यार करना भगवान का चेहरा देखने जैसा है। जो एक स्कूल का दरवाजा खोलता है, वह एक जेल का दरवाजा बंद करता है। दुनिया में कोई भी सेना उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। पढ़ना मतलब भविष्य की खिड़की खोलना है। ज्ञान का अंत तब होता है जब हम प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है। महान कार्य अक्सर छोटी शुरुआत से होते हैं।

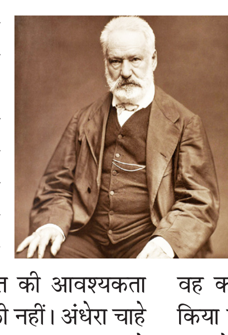

सफलता के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, केवल शक्ति की नहीं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज उसे हरा ही देता है। प्रतिकूलता ही मनुष्य को असली मनुष्य बनाती है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। जहां उम्मीद है, वहां रास्ता भी है। शांति न्याय का दूसरा नाम है। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं, बल्कि अवसर की कमी भी है। समाज की उन्नति महिलाओं के सम्मान से मापी जाती है। न्याय के बिना कानून केवल एक पिंजरा है। दयालु होना सरल है, लेकिन न्यायपूर्ण होना कठिन। हंसना वह सूरज है जो मनुष्य के चेहरे से सर्दी को भगा देता है। संगीत वह कहता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भविष्य के कई नाम हैं: कमजोरों के लिए यह 'असंभव' है, डरपोक के लिए 'अज्ञात', और बहादुर के लिए 'अवसर'। हमारी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता हैं। परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। अंतरात्मा मनुष्य के भीतर भगवान की आवाज है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

जीवन का संतुलन और 'यह भी बीत जायेगा' का दर्शन

परिवर्तन संसार का शाश्वत नियम है और इस सत्य को एक सम्राट और उसके जादुई छल्ले की कहानी से सबसे सटीक रूप में समझा जा सकता है। जब एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार से एक ऐसी पंक्ति लिखने को कहा जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में काम आए, तो एक फकीर के सुझाव पर उस छल्ले पर लिखवाया गया—"यह भी बीत जायेगा।" यह छोटा सा वाक्य वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र है। जब सम्राट युद्ध हारकर पहाड़ियों में छिपा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब इन शब्दों ने उसे मानसिक पतन से बचाया और उसके विचलित मन को शांत कर दिया। वहीं, जब वह पुनः विजयी होकर वैभव के शिखर पर पहुँचा, तब इन्हीं शब्दों ने उसे याद दिलाया कि यह गौरव भी स्थायी नहीं है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन जल की धारा के समान निरंतर गतिशील है। इसलिए न तो दुख में हताश होकर स्वयं को मिटाना चाहिए और न ही सुख में अति-उत्साहित होकर संतुलन खोना चाहिए। जो व्यक्ति इस क्षणभंगुरता को समझ लेता है, वह जीवन के हर कठिन संदर्भ में स्थिर रहता है।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके संचित धन से नहीं, बल्कि उसके गुणों, विद्या और श्रेष्ठ आचरण से आंका जाता है। शास्त्रों का मत है कि अधम वर्ग के लोग केवल धन की लालसा रखते हैं, मध्यम वर्ग धन और मान दोनों, किंतु उत्तम वर्ग के लिए आत्म-सम्मान ही वास्तविक संपत्ति है। जिस प्रकार बिना सुगंध के पलाश का फूल केवल देखने में आकर्षक होता है, उसी प्रकार विद्याहीन व्यक्ति चाहे कितने ही ऊँचे कुल का क्यों न हो, वह विद्वानों के समाज में शोभा नहीं पाता। हमारे विचार हमारे द्वारा ग्रहण किए गए अन्न की शुद्धता से प्रभावित होते हैं। जैसा अन्न, वैसा मन। सात्विक भोजन सात्विक बुद्धि और निर्मल विचारों को जन्म देता है।

इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शुद्ध विचारों का बीजारोपण अनिवार्य है, क्योंकि आज के विचार ही भविष्य के कर्मों का विशाल वृक्ष बनते हैं।

उचित सोच, सही समय और सार्थक प्रयास का संगम ही वह मार्ग है जहाँ सफलता दासी बन जाती है। ईश्वर का वास्तविक वास किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के 'भाव' में होता है। सच्ची शांति बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि मन के संतोष और करुणा से प्राप्त होती है। शास्त्रों में लोभ को भयानक रोग और संतोष को सबसे बड़ा सुख माना गया है। जब मनुष्य अहंकार त्यागकर परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, तो पर्वत जैसी समस्याएं भी नगण्य हो जाती हैं। प्रायः लोग दुख में ईश्वर को याद करते हैं परंतु सुख में विस्मृत कर देते हैं; यदि सुख में भी वह स्मृति बनी रहे, तो दुख का प्रवेश ही दुर्लभ हो जाए। पूर्ण विश्वास और भक्ति वह औषधि है जो मनुष्य को समस्त भयों से मुक्त कर अभय प्रदान करती है।

प्रभु शरणागत वत्सल हैं, जो सच्चे हृदय की पुकार पर भक्त का हर बोझ स्वयं उठा लेते हैं। भारतीय संस्कृति में भवन निर्माण के समय नींव में शेषनाग और कलश स्थापित करने के पीछे गहरा आध्यात्मिक आधार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी है। नींव में चांदी के नाग का पूजन इस विश्वास का प्रतीक है कि जिस प्रकार शेषनाग ने पृथ्वी को संभाल रखा है, वैसे ही वे भवन को मजबूती देंगे। यह परंपरा हमें स्मरण कराती है कि हमारे भौतिक अस्तित्व का आधार भी आध्यात्मिक शक्तियों में निहित है।

अपने विचार

नेहरू जी ने 45 करोड़ जनता को अपनी जिम्मेदारी बताई थी लेकिन उनके यह शब्द जनता के साथ धोखा हैं। पंचशील की आड़ में किस तरह से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल में खत लिखकर चीन को स्थाई सदस्यता देने की वकालत की गई थी।

नितिन नवीन
अध्यक्ष, भाजपा

'हिंदूओं को कम से कम चार बच्चे पैदा करना चाहिए. हमारी तो शादी नहीं हुई, तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे ही कि बाबा आपका क्या योगदान है. जब हमारा ब्याह हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में योगदान देंगे।

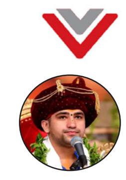

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री
बागेश्वर धाम

भाजपा की यह पुरानी कार्यशैली रही है कि जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे झूठे आरोपों से डराने, दबाने और खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह एक 'नकारात्मक आपराधिक त्रगुट' की तरह काम कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल कर धन कमाना है।

अखिलेश यादव
अध्यक्ष,सपा

दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करना भारत की राजधानी की सभ्यतागत पहचान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा, जिससे राष्ट्रीय गौरव मजबूत होगा और विश्व के सामने भारत की प्राचीन विरासत और भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होगी।

प्रवीन खंडेलवाल
सांसद, दिल्ली

अपने विचार
डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com कार्यकारी संपादक : अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए जिमेदार).

ब्रीफ न्यूज़

पुणे–नाशिक सेमी हाईस्पीड रेल परियोजना पर संकट

मुंबईः बहुप्रतीक्षित पुणे–नाशिक सेमी हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर बड़ी तकनीकी अड़चन सामने आई है। केंद्र सरकार के बफर ज़ोन से जुड़े आपत्ति के कारण अब इस रेल मार्ग में बदलाव करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को विधान परिषद में जानकारी दी कि वैकल्पिक मार्ग तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित रेल मार्ग जिस क्षेत्र से गुजरने वाला है, वहां एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला (GMRT) स्थित है, जिसका एक निर्धारित बफर ज़ोन है। इस क्षेत्र से रेल लाइन ले जाने पर तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस आधार पर केंद्र सरकार ने पुराने मार्ग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार अब केंद्र से चर्चा कर एक अनुभवी तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त करेगी। यह समिति अगले तीन से चार महीनों तक वेधशाला क्षेत्र का गहन अध्ययन करेगी। रिपोर्ट में यह देखा जाएगा कि मार्ग में न्यूनतम बदलाव करते हुए अधिकतम गांवों को रेल नेटवर्क से कैसे जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम मार्ग तय किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से प्रारंभ में 'वाया शिर्डी' वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया था। हालांकि, इस मार्ग से यात्रा का समय लगभग 30 से 31 मिनट बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसी कारण कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस विकल्प का विरोध किया है और तीसरे व्यवहार्य मार्ग की मांग की है।

2025 में 41 बाघों की हुई मौत

मुंबईः महाराष्ट्र में वर्ष 2025 के दौरान अब तक 41 बाघों की मौत होने की चौंकाने वाली जानकारी वन मंत्री ने विधानसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से दी। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 28 बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, जबकि शेष 13 बाघ मानवीय हस्तक्षेप और दुर्घटनाओं का शिकार बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक 8 बाघ विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए, 4 बाघों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई, जबकि 1 बाघ शिकार का शिकार बना। इन घटनाओं ने राज्य में वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने बाघों की बढ़ती मौतों को देखते हुए वन क्षेत्रों से गुजरने वाली रेलवे और सड़कों पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में वन्यप्राणियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अंडरपास और ओवरपास बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वन क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दल' को सक्रिय किया गया है। वन परिक्षेत्र स्तर पर मुखबिरों का जाल बिछाया गया है और वायरलेस संचार व्यवस्था के साथ जांच चौकियां स्थापित कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाघों के आवागमन मार्गों पर कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं।

समृद्धि महामार्ग से सीधे जुड़ेगी मायानगरी

6,748 करोड़ के नए एलीवेटेड हाईवे को मंजूरी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने मुंबई और ठाणे के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात दी है। 'समृद्धि महामार्ग' को सीधे मुंबई से जोड़ने के लिए 6,748 करोड़ रुपये के एलीवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्रीय ट्रैफिक को नई गति मिलेगी।

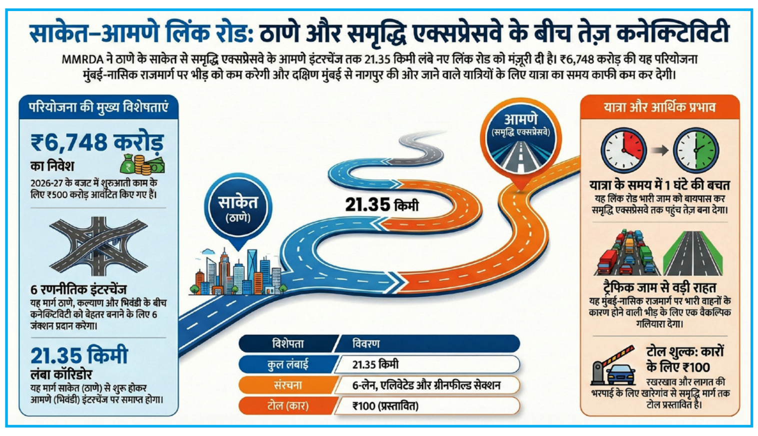

साकेत से आमने तक बनेगा नया कॉरिडोर

यह एलीवेटेड हाईवे ठाणे के साकेत से शुरू होकर आमने तक जाएगा। इससे भिवंडी, अंजुर और आसपास के इलाकों में लगने वाले घंटों के ट्रैफिक जाम से यात्रियों को राहत मिलेगी और सफर का समय काफी घटेगा।

21.35 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड मार्ग

परियोजना की कुल लंबाई 21.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 12.55 किलोमीटर हिस्सा एलीवेटेड और 8.80 किलोमीटर ग्रीनफील्ड होगा। यह पूरा मार्ग छह लेन का हाई-स्पीड कॉरिडोर बनेगा, जिससे भारी और हल्के दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही आसान होगी।

टोल प्रणाली से होगी लागत की भरपाई

MMRDA ने परियोजना के लिए टोल प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा है। संभावित दरों के अनुसार कारों से 100 रुपये, छोटी बसों से 160 रुपये, ट्रक और बड़ी बसों से 340 रुपये तथा मल्टी-एक्सल भारी वाहनों से 645 रुपये टोल लिया जा सकता है। इसमें हर साल 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का भी सुझाव दिया गया है।

127 हेक्टेयर जमीन और सरकार की मंजूरी

इस परियोजना के लिए लगभग 127 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिसमें अधिकतर निजी भूमि शामिल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और MMRDA आयुक्त के निर्देशों के बाद इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह हाईवे समय की बचत के साथ ईंधन खपत घटाएगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालेगा।

आमने का ट्रैफिक जाम होगा इतिहास

फिलहाल नागपुर–मुंबई समृद्धि महामार्ग से आने वाले वाहनों को आमने क्षेत्र में भारी जाम का सामना करना पड़ता है। भिवंडी और आसपास के औद्योगिक गोदामों के कारण यहां ट्रकों की आवाजाही ज्यादा रहती है। नया कॉरिडोर शुरू होने के बाद वाहन बिना रुके सीधे ठाणे और मुंबई में प्रवेश कर सकेंगे।

काजू किसानों के लिए आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

कोंकण के काजू उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए कच्चे काजू पर आयात शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कुडाल–मालवण विधानसभा क्षेत्र के निलेश राणे ने बुधवार (25 फरवरी) को विधानसभा में की। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने काजू किसानों की बदहाली, अवैध वृक्ष कटाई, गोहत्या प्रतिबंध और बढ़ते नशा कारोबार जैसे मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरा।

गोवा की तर्ज पर मूल्य तय करने की मांग

विधायक ने कहा कि पड़ोसी राज्य गोवा में काजू का भाव 170 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा नीति के कारण कोंकण के काजू उत्पादक आर्थिक संकट में फंस गए हैं और सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

अफ्रीकी काजू से गिरा बाजार भाव

निलेश राणे ने कहा कि कोंकण में कई युवा नौकरी छोड़कर काजू उत्पादन से जुड़े हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू के आयात के कारण स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आयातित काजू को स्थानीय काजू में मिलाने से बाजार भाव गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 तक काजू पर आयात शुल्क 18 प्रतिशत था, जो अब घटकर केवल 2.5 प्रतिशत रह गया है। किसानों को बचाने के लिए इसे कम से कम 20 प्रतिशत तक बढ़ाना जरूरी है।

1 मार्च से मुंबई–विजयदुर्ग रो-रो सेवा शुरू

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में मुंबई और कोकण को जलमार्ग से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने रो-रो जलवाहतूक सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रविवार, 1 मार्च 2026 से मुंबई से विजयदुर्ग के बीच रो-रो सेवा शुरू की जाएगी। मत्स्य व्यवसाय एवं बंदर विकास मंत्री नितेश राणे ने बताया कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों और सावधानियों के साथ यह सेवा प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में मुंबई से रत्नागिरी और महाड जैसे मार्गों पर भी जलवाहतूक शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

शिमगोत्सव यात्रियों को बड़ा फायदा

शिमगोत्सव के दौरान मुंबई से कोकण जाने वालों के लिए रो–रो सेवा एक सुरक्षित, आरामदायक और तेज विकल्प साबित होगी। नागरिकों का इस सेवा को सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है और आगे भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रो–रो सेवा के जरिए मुंबई को अन्य राज्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे पर्यटन, रोजगार और कृषि क्षेत्र को गति मिलेगी। विशेष रूप से आम, काजू और मछली व्यवसाय को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

दर और समय-सारिणी ऑनलाइन उपलब्ध

मुंबई–विजयदुर्ग रो–रो सेवा के किराए और समय–सारिणी की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और यात्रियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।

पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में कदम

मंत्री नितेश राणे ने कहा कि पर्यावरण–संतुलित विकास मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए रो–रो सेवा की योजना बनाई गई है, जिससे समय की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा।

नवी मुंबई महानगरपालिका ने वसूले 650 करोड़ रुपये संपत्ति कर

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपालिका के संपत्ति कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 650 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है। इस दौरान डिजिटल माध्यम से कर चुकाने वाले नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे राजस्व संग्रह में तेजी आई है।

कई डिजिटल विकल्प किए गए उपलब्ध

महानगरपालिका की ओर से UPI, QR कोड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/RTGS और IMPS जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। घर बैठे सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से भुगतान संभव होने के कारण नागरिक तेजी से ऑनलाइन माध्यम अपना रहे हैं। बकायेदारों को एसएमएस और व्हाट्सऐप के जरिए भुगतान लिंक भी भेजे जा रहे हैं।

ऑनलाइन माध्यम को मिल रहा अधिक समर्थन

महापालिका के अनुसार 1,82,894 करदाताओं से कुल 650 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इनमें 62 प्रतिशत करदाताओं ने डिजिटल माध्यम से 383 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि 38 प्रतिशत नागरिकों ने ऑफलाइन तरीके से 267 करोड़ रुपये का संपत्ति कर भरा है।

बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू

बार–बार सूचना देने के बावजूद कर जमा न करने वालों के खिलाफ संपत्ति कर विभाग ने जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी विभागीय कार्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और क्षेत्रवार योजना बनाकर बकायेदारों की सूची अपडेट की गई है।

77 संपत्तियों पर कार्रवाई, आगे और सख्ती

अब तक 77 संपत्तियों पर कार्रवाई कर करीब 39 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा 1608 बड़े बकायेदारों को 7 दिन और 48 घंटे पहले की जब्ती नोटिस जारी की गई है। फिलहाल औद्योगिक संपत्तियों पर कार्रवाई चल रही है और आगे व्यावसायिक व वाणिज्यिक संपत्तियों पर भी कदम उठाए जाएंगे। महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने नागरिकों से समय पर संपत्ति कर भरने की अपील करते हुए कहा कि लगातार नोटिस के बाद भी भुगतान न करने वालों पर सीधे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

1350 चालक बने वेलफेयर बोर्ड के सदस्य

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की सदस्यता मुहिम को तेज़ प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 1,350 रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर इस बोर्ड से जुड़ चुके हैं। संगठित होकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने की पहल को ड्राइवरों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देश पर बोर्ड सदस्यों के आधिकारिक पहचान पत्र तैयार किए गए। मंगलवार को ठाणे आरटीओ कार्यालय में इन पहचान पत्रों का वितरण किया गया, जहां ड्राइवरों में खासा उत्साह देखने को मिला।

सदस्यों से पहचान पत्र लेने की अपील

बोर्ड की ओर से सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने–अपने आरटीओ कार्यालय से पहचान पत्र प्राप्त करें। साथ ही, जो रिक्शा–टैक्सी चालक अब तक सदस्य नहीं बने हैं, उनसे जल्द से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है।

सम्मान और सुरक्षा की दिशा में कदम

ड्राइवरों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल केवल पहचान पत्र वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी का माध्यम भी बन रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अधिक संख्या में ड्राइवर इस बोर्ड से जुड़ेंगे और संगठित शक्ति के जरिए अपने भविष्य को मजबूत करेंगे।

3 जुलाई से शुरू हुई सदस्यता प्रक्रिया

मुख्य आरटीओ अधिकारी हेमांगिनी पाटिल के मार्गदर्शन में बोर्ड की सदस्यता प्रक्रिया 3 जुलाई 2025 से शुरू की गई थी। सदस्य बनने के लिए 800 रुपये की पंजीकरण व सदस्यता फीस तय की गई है। फीस जमा करने वाले ड्राइवरों के पहचान पत्र तैयार कर लिए गए हैं, जबकि शेष कार्ड संबंधित आरटीओ कार्यालयों को डाक से भेजे जाएंगे।

यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रेलवे के भुसावल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में ही करें। हाल के दिनों में मामूली कारणों से चेन खींचने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिन पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।

मामूली कारणों से हो रहा दुरुपयोग

रेलवे के अनुसार, कई मामलों में यात्री गलती से, ट्रेन छूट जाने पर, मोबाइल फोन गिर जाने या अन्य छोटे कारणों से अलार्म चेन खींच देते हैं। इस तरह का दुरुपयोग न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यात्रा व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

कई ट्रेनों पर पड़ता है असर

अलार्म चेन पुलिंग का गलत इस्तेमाल सिर्फ उसी ट्रेन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे आने वाली अन्य ट्रेनों की समय–सारणी भी बिगड़ जाती है। एक या दो यात्रियों की सुविधा के लिए सैकड़ों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है।

यात्रियों से जिम्मेदारी निभाने की अपील

मंडल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय से स्टेशन पहुंचें और अनावश्यक कारणों से अलार्म चेन न खींचें। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत यह दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए स्टेशन पर बैटरी चालित वाहन और व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि उन्हें ट्रेन पकड़ने में कोई परेशानी न हो।

495 मामलों में वसूला गया जुर्माना

भुसावल मंडल में दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 के बीच अलार्म चेन पुलिंग के कुल 495 मामले दर्ज किए गए। इनमें 426 लोगों को दोषी पाया गया और कुल 1,43,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। मंडल प्रशासन इन घटनाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

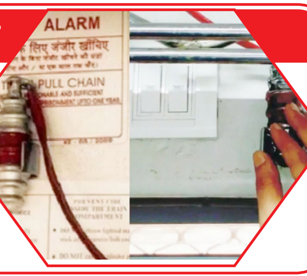

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष मेहनत रंग लाएगी। कार्य की प्रशंसा होगी। यात्रा सफल रहेगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। लाभ होगा। वाहन क्रय करने के योग बनेंगे। इच्छाशक्ति का लाभ मिलेगा। पारिवारिक वातावरण से आशान्वित रहेंगे।

वृष पुराना रोग उभर सकता है। शोक समाचार मिल सकता है, धैर्य रखें। मेहनत अधिक होगी। थकान रहेगी। व्यर्थ खींचतान में नुकसान संभव है। आर्थिक मामलों में विश्वास, भरोसे में नहीं रहें। दिन प्रतिकूल रहेगा। स्वभावगत चंचलता में कमी करना होगी।

मिथुन विवेक से कार्य करें। लाभ होगा। सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक व्यापारिक योजनाओं को अंजाम दें। विद्यार्थी शिक्षा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करेंगे। यात्रा न करें। पुराना रोग उभर सकता है। कार्य में लापरवाही व जल्दबाजी न करें। कुसंगति से बचें।

कर्क विवेक से कार्य करें। दूसरों पर विश्वास न करें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यापारिक प्रतिष्ठा, लेन-देन अन्य कानूनी परेशानी संभव है। परिवार में किसी से विवाद होने की आशंका है। अनिश्चितता का वातावरण रहेगा। अपने कार्य–निर्णय गुप्त रखें।

सिंह उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। व्यवसाय ठीक चलेगा। बड़े एवं प्रतिष्ठित लोगों से संबंधों का लाभ मिल सकेगा। जोखिम, जवाबदारी के कामों में सावधानी आवश्यक है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा।

कन्या पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी। शुभ समाचार मिलेंगे। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। उत्तेजित न हों। लाभ होगा। रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी। महत्व के मामले सुलझेंगे। घर में मूल्यवान वस्तुओं को संभालना होगा। विरोधी, शत्रु शांत रहेंगे।

तुला स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। आशानुरूप आमदनी होगी। व्यापार–व्यवसाय में अनुभव, निवेश में सफलता मिलेगी। समय का सदुपयोग होगा।

वृश्चिक बेरोजगारी दूर होगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। घर–बाहर प्रसन्नता रहेगी। नौकरी, रोजगार में उन्नति, सहयोग संभव है। आवश्यक मार्गदर्शन मिलेगा। संतान पक्ष के स्थायित्व की बात बनेगी।

धनु परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। प्रसन्नता रहेगी। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। कानूनी बाधा दूर होगी। अपरिचित व्यक्तियों के सहयोग से आत्मविश्वास का संचार होगा। खर्चों में कमी का प्रयास करना होगा। लाभकारी निवेश बढ़ेगा।

मकर रुका हुआ धन प्राप्त होगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। थकान रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में पद, स्थिति से लाभान्वित हो पाएँगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक मामलों में लोभ, प्रलोभन से बचें। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा।

कुंभ कार्यस्थल पर सुधार होगा। नए अनुबंध हो सकते हैं। मान–सम्मान बढ़ेगा। घर–बाहर प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। कार्य में प्रगति, उत्साह रहेगा। दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं आएगी। कर्ज, लेन–देन कम होगा। भेंट, उपहार की प्राप्ति होगी।

मीन धर्म–कर्म में रुचि रहेगी। महत्वपूर्ण व्यक्ति सहायता को आगे आएंगे। कार्यसिद्धि होगी। व्यवसाय लाभदायक रहेगा। उत्साहपूर्वक व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करेंगे। अचानक धन की प्राप्ति संभव है। कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ेगी। अनुज सहयोग करेंगे।

शुक्र के पीछे छूट जाने की पीड़ा: जब सूर्य और बुध घर में व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन हृदय खाली रह जाता है

प्रियंका जैन

जब जन्म कुंडली में शुक्र के बाद सूर्य और सूर्य के बाद बुध स्थित होते हैं, तो यह केवल ग्रहों की भौतिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह परिवार की आंतरिक संरचना, संबंधों की दिशा और भावनात्मक वास्तविकता का एक गहरा संकेत होता है। यह योग एक ऐसी जीवन कथा को दर्शाता है जिसमें बाहरी रूप से सब कुछ व्यवस्थित, तर्कसंगत और सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म खालीपन, एक अनकही दूरी और एक अधूरापन मौजूद रहता है।

वैदिक ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने स्पष्ट किया है कि शुक्र केवल धन या भोग का कारक नहीं है, बल्कि वह उस धन को सुख में बदलने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र पीछे छूट जाता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि जीवन में संसाधन तो आते हैं, लेकिन वे आत्मा को संतुष्टि देने में सक्षम नहीं होते।

ऐसे घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सबसे अधिक सक्षम होता है, वही धीरे-धीरे सूर्य की भूमिका ग्रहण कर लेता है। सूर्य का स्वभाव स्वाभाविक रूप से केंद्र में रहने का होता है। वह प्रकाश देता है, दिशा देता है और अपने चारों ओर सब कुछ व्यवस्थित करता है। लेकिन सूर्य का एक और पक्ष भी है— वह अकेला होता है। वह अपने आसपास के ग्रहों को अपनी परिक्रमा में रखता है, लेकिन वह स्वयं किसी के चारों ओर नहीं घूमता।

जब परिवार में कोई व्यक्ति सूर्य बन जाता है, तो वह निर्णय लेने की शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। उसके निर्णयों में आत्मविश्वास होता है, दृढ़ता होती है, लेकिन कभी-कभी उनमें दूसरों की भावनाओं के लिए स्थान नहीं होता। इसके बाद बुध की भूमिका शुरू होती है। बुध तर्क का ग्रह है। वह हर निर्णय को बुद्धि, शब्द और लॉजिक के माध्यम से सही साबित करने की क्षमता देता है। यहीं से परिवार की एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। पहले निर्णय लिया जाता है, फिर उस निर्णय को तर्कों के माध्यम से उचित ठहराया जाता है। लेकिन उस निर्णय से पहले जो भावनाएँ थीं, जो इच्छाएँ थीं, जो संबंधों की सूक्ष्म तरंगें थीं, वे कहीं पीछे छूट जाती हैं। वह शुक्र था— जो अब सबसे पीछे है।

शुक्र का पीछे होना यह दर्शाता है कि संबंधों की प्राथमिकता धीरे-धीरे कम हो रही है। अब प्राथमिकता है व्यवस्था, नियंत्रण और तर्क। पैसा आ रहा है, सुविधाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन उन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए जो भावनात्मक एकता चाहिए, वह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आसमान में केवल एक सूर्य होता है और एक चंद्र होता है। जब केवल एक सूर्य होता है, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन जब घर में हर व्यक्ति सूर्य बनने की कोशिश करता है, तो संतुलन टूटने लगता है। हर कोई निर्णय लेना चाहता है, हर कोई अपनी बात को अंतिम मानना चाहता है, हर कोई अपने तर्क को सही साबित करना चाहता है।

जापान में निवेश का 'मेगा डे': यूपी में उद्योगों को नई रफ्तार

11,000 करोड़ के MoU पर मुहर

एजेंसी । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे की शुरुआत बड़े निवेश संकेतों के साथ हुई। पहले ही दिन करीब 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए, जिससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। पहले दिन के ये समझौते भारत-जापान औद्योगिक साझेदारी को नई दिशा देने के संकेत हैं। सरकार का मानना है कि इन निवेशों से प्रदेश की विनिर्माण क्षमता, रोजगार सृजन और तकनीकी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इन प्रमुख कंपनियों से हुआ करार

दौरे के दौरान जिन प्रमुख कंपनियों के साथ करार हुए, उनमें कुबोता कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएंडओ ग्रुप, फूजी जैपनीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्रा. लि. शामिल हैं। ये समझौते कृषि यंत्र निर्माण, औद्योगिक मशीनरी निर्माण, औद्योगिक प्रिंटिंग एवं ग्राफिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं।

कृषि-मशीनरी क्षेत्र की कंपनी है कुबोता

1890 में स्थापित कुबोता कॉर्पोरेशन कृषि एवं औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र की वैश्विक दिग्गज कंपनी है, जिसका मुख्यालय ओसाका में है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इंजन और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ-साथ जल प्रबंधन समाधान में इसकी मजबूत पकड़ है। भारत में एस्कॉर्ट्स कुबोता के माध्यम से कंपनी पहले से सक्रिय है और अब यूपी में विनिर्माण विस्तार की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

ईवी और एयरोस्पेस को मिलेगा बूस्ट

स्पार्क मिंडा समूह की मिंडा कॉर्पोरेशन ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स—मैक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग हार्नेस, सेंसर और ईवी समाधान—के क्षेत्र में अग्रणी है। वहीं जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री (जेएई) ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एडवांस कनेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस समाधान उपलब्ध कराती है।

तकनीकी साझेदारी को मिलेगा बल

नागासे एंड कंपनी के साथ सहयोग से केमिकल्स, एडवांस्ड मैटेरियल्स और मोबिलिटी सॉल्यूशंस में तकनीकी साझेदारी को बल मिलेगा। इन करारों से यूपी में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च स्तरीय कंपोनेंट निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रिंटिंग इंक और कोटिंग में एक्सपर्ट 'सीको'

सीको एडवांस उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन प्रिंटिंग इंक और कोटिंग सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है, जिनका उपयोग ऑटोमोटिव डीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल और औद्योगिक ग्राफिक्स में होता है।

Ex CM चंपाई सोरेन के पोते की संदिग्ध मौत

▶▶ दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था पूर्व मुख्यमंत्री का पोता

एजेंसी । कुल्लू

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

मुंह से निकल रहा था झाग

डीएसपी मनाली क्षमादत्त शर्मा के अनुसार, वीर के एक मित्र—उत्तर प्रदेश निवासी अग्नय—ने बताया कि दोपहर लगभग ढाई बजे कमरे से गिरने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो वीर बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा था। उसे तत्काल निजी वाहन से मनाली अस्पताल पहुंचाया गया।

सिरदर्द होने पर आनलाइन मंगवाई थी दवा

जानकारी के मुताबिक, वीर सोरेन 22 फरवरी को दोस्तों के साथ मनाली घूमने पहुंचे थे। सभी सिमसा क्षेत्र स्थित एक होम-स्टे में ठहरे हुए थे। 23 फरवरी को समूह सोलंग-सेथन इलाके में घूमने गया और शाम को वापस लौट आया। अगले दिन दोपहर करीब साढ़े बारह बजे जब मित्र बाहर से लौटे, तो वीर कमरे में सोता मिला। जगाने पर उसने तेज सिरदर्द की शिकायत की। साथियों ने ऑनलाइन दवा मंगवाकर उसे दी, जिसके बाद वह दोबारा सो गया।

परिजनों के आने पर होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने शव को मनाली के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके आधार पर मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

बसपा MLA उमाशंकर सिंह के आवास पर आईटी का छापा

▶▶ बहुजन समाज पार्टी से इकलौते विधायक हैं उमाशंकर

एजेंसी । लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने गोमतीनगर स्थित घर और कार्यालय दोनों स्थानों पर एक साथ पहुंचकर तलाशी शुरू की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती रही और परिसर को अस्थायी रूप से सील कर आवागमन सीमित कर दिया गया।

डायरी में मिले नौकरशाहों के नाम

सूत्रों के अनुसार तलाशी के दौरान एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें कथित रूप से कई वर्तमान और सेवानिवृत्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं।

गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उमाशंकर

हालांकि, विभाग की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब विधायक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके दो ऑपरेशन हो चुके हैं। छापेमारी की खबर के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

बरेली रूट पर दौड़ेंगी 48 होली स्पेशल गाड़ियां

बरेली। रंगों के त्योहार पर घर वापसी की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरेली रूट पर बड़ी राहत दी है। 48 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय किया गया है, जिससे नियमित ट्रेनों पर दबाव घटने लगा है और वेटिंग लिस्ट में भी राहत दिख रही है।

सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05575/05576 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 11 मार्च को सहरसा से और 10 व 17 मार्च को आनंद विहार से चलेगी। यह ट्रेन अगले दिन शाम 6:34 बजे बरेली पहुंचेगी।

पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल

इसी क्रम में 05579/05580 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल 6 से 15 मार्च के बीच चयनित तिथियों पर संचालित होगी और शाम 6:34 बजे बरेली पहुंचेगी।

₹350 करोड़ से चमकेगा ग्रीन पार्क

कानपुर। ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम अब नए कलेवर में नजर आएगा। 350 करोड़ रुपये की पुनर्विकास योजना के साथ इसे विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। खास बात यह कि स्टेडियम का किराया प्रदेश में सबसे कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिससे बड़े क्रिकेट आयोजनों की राह आसान होगी। कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने बुधवार को निरीक्षण के दौरान कहा कि ग्रीनपार्क सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि प्रदेश की खेल पहचान है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए इसे फिर से प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है

स्वामी शिवानंद भारती से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

▶▶ होटल कारोबारी समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

▶▶ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा प्रकरण

हरिद्वार। धर्मनगरी में एक संत से पांच करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने स्वामी शिवानंद भारती की शिकायत पर होटल कारोबारी सन्नी कपूर और उसके सहयोगी रोहित कोहली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपीपक्ष ने क्षतिपूर्ति देने का रखा प्रस्ताव

आरोप है कि 17 मई 2024 को आर्थिक असमर्थता जताते हुए 200 रुपये प्रति वर्गफुट क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव रखा गया।

परिचितों के नाम किया भूमि का एक हिस्सा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि 30 अगस्त 2025 को आरोपियों ने संपत्ति का एक हिस्सा अपने परिचितों के नाम स्थानांतरित कर दिया। साथ ही 19 सितंबर 2025 को फोन कर आधी संपत्ति और पांच करोड़ रुपये की मांग की गई। रकम न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।

व्यापार जगत

बदलेगा देश की आर्थिक सेहत मापने का पैमाना

▶▶ 27 फरवरी को जारी किए जाएंगे तीसरी तिमाही के नए आंकड़े

एजेंसी । नई दिल्ली

देश की आर्थिक सेहत मापने का तरीका अब बदलेगा। 27 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़े नए आधार वर्ष के साथ जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही जीडीपी गणना की पूरी श्रृंखला में संरचनात्मक बदलाव लागू होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अब 2011-12 की जगह 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर आंकड़े जारी करेगा। यह बदलाव अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को अधिक सटीक तरीके से प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

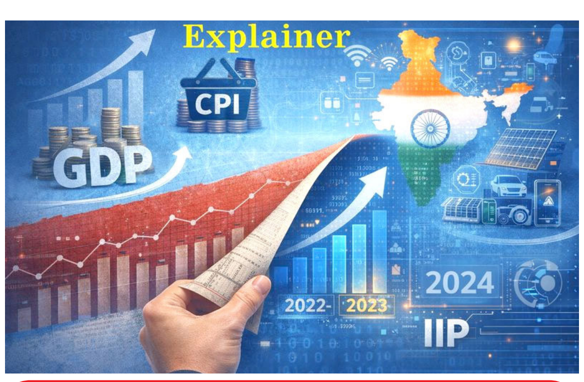

डबल डिफ्लेशन पद्धति का उपयोग

नई श्रृंखला में 'डबल डिफ्लेशन' पद्धति का उपयोग किया जाएगा, जिससे उत्पादन और मूल्य स्तर के आकलन में अधिक परिशुद्धता आएगी। इसके अलावा 500-600 वस्तुओं को शामिल कर डेटा कवरेज को व्यापक बनाया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिए भी 2022-23 आधार वर्ष लागू रहेगा। संभावना है कि इसी दिन मंत्रालय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान भी जारी करे। नए बेस ईयर के कारण पहली और दूसरी तिमाही के पहले जारी किए गए आंकड़ों में संशोधन संभव है।

वैश्विक स्तर पर ठोस उपस्थिति दर्ज करा रहा भारत : कुमारस्वामी

एजेंसी । नई दिल्ली

अवसंरचना और औद्योगिक विस्तार को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने स्पष्ट कहा कि पूंजीगत व्यय में आक्रामक बढ़ोतरी भारत के निर्माण उपकरण उद्योग को वैश्विक नेतृत्व की कतार में ला सकती है। उनका मानना है कि मजबूत वित्तपोषण ढांचा और दीर्घकालिक निवेश रणनीति ही देश की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को ठोस आधार दे सकती है। छठे वार्षिक निर्माण उपकरण वित्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि भारत तेजी से विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। यह प्रगति बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार, विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती और निरंतर सार्वजनिक निवेश से संचालित हो रही है।

1.68 लाख करोड़ देकर बंद हुआ बाजार

▶▶ उछाल से मुनाफावसूली तक : दिनभर के झटकों के बाद बाजार सपाट बंद

एजेंसी । मुंबई

तेज शुरुआत, दोपहर की बिकवाली और अंत में संभलाव—ऐसे उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद शेयर बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। BSE Sensex एक समय 700 अंक तक उछल गया था, लेकिन बाद में मुनाफावसूली हावी हो गई। अंततः सेंसेक्स 50.15 अंक यानी 0.06% की हल्की बढ़त के साथ 82,276.07 पर बंद हुआ। वहीं Nifty 50 57.85 अंक (0.23%) चढ़कर 25,482.50 पर बंद हुआ।

ब्रॉडर मार्केट ने दिखाई ताकत

मुख्य सूचकांक भले ही सीमित दायरे में रहे, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बेहतर खरीदारी दिखी। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स करीब 0.5% और स्मॉलकैप इंडेक्स 1% तक मजबूत होकर बंद हुए।

निवेशकों की संपत्ति में इजाफा

बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 467.32 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले सत्र में 465.64 लाख करोड़ रुपये था। यानी एक दिन में निवेशकों की संपत्ति करीब 1.68 लाख करोड़ रुपये बढ़ी। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर बढ़त में बंद हुए। HCL Technologies करीब 2.8% की तेजी के साथ शीर्ष पर रहा। इसके अलावा Tata Steel, TCS, Inter Globe Aviation और Sun Pharmaceutical Industries में 1.8% से 2.6% तक की बढ़त दर्ज हुई। वहीं 11 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। Reliance Industries 2.23% टूटकर टॉप लूजर रहा।

स्टील इंडस्ट्री के दिग्गज जतिंदर मेहरा नहीं रहे

86 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, इस्पात और खनन परियोजनाओं को दी नई ऊंचाई

नई दिल्ली। देश के इस्पात और धातु क्षेत्र के वरिष्ठ उद्योगपति जतिंदर मेहरा का 24 फरवरी को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उद्योग जगत में उन्हें दूरदर्शी रणनीतिकार और मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में याद किया जाता है। एस्सार ग्रुप (Essar Group) ने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि मेहरा धातु एवं खनन प्रभाग में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने समूह की इस्पात और खनन परियोजनाओं को नई दिशा दी और कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

वैश्विक बाजार में दर्ज कराई उपस्थिति

मेहरा के कार्यकाल में हजीरा में इस्पात उत्पादन क्षमता विस्तार और ओडिशा के प्रस्तावित पारादीप इस्पात संयंत्र जैसी एकीकृत परियोजनाओं को गति मिली। उनके नेतृत्व में समूह ने वैश्विक इस्पात बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत की।

जल्द आएगा PhonePe का आईपीओ

12000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में कंपनी, सेबी ने आईपीओ को दी हरी झंडी

एजेंसी । नई दिल्ली

नई दिल्ली। भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में बड़ा नाम बन चुकी PhonePe अब पूंजी बाजार की ओर कदम बढ़ा रही है। Walmart समूह की यह पहली भारतीय इकाई होगी, जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए शेयर बाजार में दस्तक देगी। कंपनी करीब 12,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है और इसे बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से हरी झंडी भी मिल चुकी है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित होगा। यानी IPO से प्राप्त धनराशि कंपनी के खाते में नहीं आएगी, बल्कि मौजूदा निवेशक और प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर आंशिक या पूर्ण निकास लेंगे। कंपनी ने सितंबर 2025 में गोपनीय मार्ग से आवेदन किया था और अब संशोधित दस्तावेज दाखिल कर प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है।

UPI से यूनिकॉर्न तक का सफर

करीब एक दशक पहले UPI-आधारित भुगतान ऐप के रूप में शुरू हुई PhonePe आज देश के अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में शामिल है। इसके 65 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 4.7 करोड़ से ज्यादा व्यापारी इससे जुड़े हैं। इसकी पहुंच महानगरों से आगे बढ़कर छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों तक फैली है।

जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत से ही खुलेगी भारत की राह

आमने-सामने

कुल मैच	: 13
भारत जीता	: 10
जिम्बाब्वे जीता	: 3

▶▶ टीम इंडिया के शीर्ष क्रम को आज खेलना होगा आक्रामक खेल

एजेंसी । चेन्नई

चैंपियन भारत की सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है। उसे अंतिम चार में पहुंचने के लिए गुरुवार को टी-20 विश्व के सुपर आठ में छुपे रुस्तम जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज के साथ अपना नेट रन रेट सुधारना होगा। दक्षिण अफ्रीका से 76 रन से हार के बाद उसका नेट रनरेट (माइनस 3.80) खराब हो गया है। इसके लिए भारतीय शीर्ष क्रम को अपना आक्रामक खेल खेलना होगा। खासकर स्पिनरों के खिलाफ। एक और गलती टीम को भारी पड़ सकती है।

सूर्य में नहीं दिख रही चमक

कप्तान सूर्यकुमार ने रन तो बनाए हैं लेकिन उनमें वैसी चमक नहीं दिख रही जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने 180 रन बनाए हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 127 रहा है जो उनके टी-20 करियर के 161 के स्ट्राइक रेट से काफी कम है। उन्हें अब आगे बढ़कर मोर्चा संभालना होगा।

सेमीफाइनल का समीकरण

- ▶▶ अगर भारत वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा देता है तो उसके चार अंक हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका भी बचे दोनों मैच जीत जाए या फिर हार जाएं तो भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।
- ▶▶ अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा देता है और जिम्बाब्वे से हार जाता है तो भी नेट रनरेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और टीम इंडिया सीधे आगे बढ़ जाएगी।
- ▶▶ अगर दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज हार जाए और जिम्बाब्वे से जीत जाए तो ऐसी स्थिति में द. अफ्रीका, भारत और वेस्टइंडीज तीनों के चार-चार अंक हो जाएंगे। तब फैसला नेट रनरेट से होगा ऐसे में भारत की मुश्किल बढ़ जाएगी।
- ▶▶ अगर भारत एक मैच जीतता है तो ऐसी स्थिति में उम्मीद तभी बचेगी जब दक्षिण अफ्रीका या वेस्टइंडीज में से कोई एक अपने तीनों मैच जीते और बाकी टीमें एक-एक जीत दर्ज करें जिससे मामला नेट रनरेट पर आएगा।

नंबर गेम

1	मुकाबला विश्व कप में दोनों ने खेला। वर्ष 2022 में खेले गए इस मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से धोया था
2	साल से जिम्बाब्वे के खिलाफ अजेय है भारतीय टीम। उसे जिम्बाब्वे से पिछली बार जुलाई 2024 में मिली थी
86	रन दूर हैं दुबे टी-20 में एक हजार रन पूरे करने से। वह 60 मैचों में 914

ताकत ही बनी कमजोरी

विश्व कप से पहले टीम की सबसे बड़ी ताकत अभिषेक अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वह चार पारियों में से सिर्फ एक में ही 15 रन बना पाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 75 और औसत 3 .75 रहा। सपाट पिचों पर ऑफ स्पिनरों के सामने दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज अपने पसंदीदा शॉट नहीं खेल पा रहा है। उनकी नाकामी टीम के लिए भारी पड़ रही है। विश्व कप से पहले वह ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। लेकिन पेट के संक्रमण के बाद से उनकी लय खो गई है। उन्हें ईशान के साथ मिलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलानी होगी।

ईशान को नहीं मिल रहा साथ

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच को छोड़ दे तो शीर्ष क्रम में ईशान किशन एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने निरंतर रन बनाए हैं। इससे उन पर काफी दबाव बन गया है। वह 193 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने स्पिनरों का भी डटकर सामना किया है। वह पिछली पारी को भुलाकर फिर से बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे।

तिलक बढ़ा रहे समस्या

तीसरे नंबर की समस्या भी टीम के लिए पहेली बन गई है। तिलक भी खुलकर नहीं खेल पा रहे। इसका भी नुकसान टीम को उठाना पड़ रहा है। अभिषेक के खराब फॉर्म के कारण तिलक को ईशान का बखूबी साथ देना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह 21 की औसत से सिर्फ 107 रन बना पाए हैं। उन्हें अब बड़ी पारी खेलनी होगी।

संजू को मिल सकता है मौका

बाएं हाथ के तीन बल्लेबाजों ईशान, अभिषेक और तिलक के सामने विरोधी टीमों ने पावरप्ले में ऑफ स्पिनरों का उपयोग किया है। शीर्ष तीन में दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। हालांकि वह खुद फॉर्म में नहीं हैं। रिंकू की गैरमौजूदगी में टीम प्रबंधन उन्हें एक और मौका दे सकता है। ऐसे में सूर्यकुमार को तीसरे और तिलक को चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है। वैसे चेपॉक की पिच से उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जिम्बाब्वे के पास उतना खतरनाक स्पिन आक्रमण भी नहीं है जिसका अभी तक भारत ने सामना किया है।

दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज के बीच रहा है कांटे का मुकाबला

▶▶ दोनों टीमों ने अपने-अपने पहले मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज की है

अहमदाबाद। टी-20 विश्व कप 2026 के 47वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का सामना 26 फरवरी (गुरुवार) को वेस्टइंडीज क्रिकेट से होगा। यह सुपर-8 चरण में ग्रुप-1 का मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने अपने-अपने पहले मुकाबलों में बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में दोनों टीमें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल की और मजबूत कदम बढ़ाना चाहेंगी।

दोनों टीमों के बीच कांटे का रहा है मुकाबला

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले खेले गए हैं। प्रोटियाज टीम को 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि 15 मैच में कैरेबियन टीम ने अपने नाम किए हैं। टी-20 विश्व कप में उनके बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें प्रोटियाज टीम काफी भारी रही है। इस टीम ने कुल 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि कैरेबियन टीम केवल एक मुकाबला जीतने में सफल रही है। ऐसे में वह अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी।

इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम

दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट में बेहद मजबूत नजर आई है। ऐसे में एडेन मार्करम और क्विंटन डिकॉक से एक बार फिर तेज और ठोस शुरुआत की उम्मीद रहेगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी पर बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी होगी, जबकि स्पिन विभाग की कमान केशव महाराज के हाथों में रहेगी।

इस संयोजन के साथ उतर सकती है वेस्टइंडीज टीम

वेस्टइंडीज ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। वह प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। उसने सुपर-8 के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराया है। वह जीत का क्रम बरकरार रखना चाहेगी। ब्रैंडन किंग और शिमरोन हेटमायर से फिर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

संभावित एकादश: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी।

संभावित एकादश: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, शरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, गुडाकेश मोती और शमार जोसेफ।

कैसा रहेगा अहमदाबाद का मौसम?

एक्यूवेदर के अनुसार, 26 फरवरी को अहमदाबाद का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 20 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है।

डोपिंग टेस्ट से बचने पर धाविका पूजा आत्माराम पर प्रतिबंध

एजेंसी । चेन्नई

एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (एआईयू) ने खुलासा किया है कि भारत की लंबी दूरी की धाविका पूजा आत्माराम पिछले साल प्रतियोगिता के दौरान होने वाले डोप परीक्षण से पहले घबराकर भाग गई थीं। यह अपराध स्वीकार करने के बाद उन पर चार के बजाय तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 30 वर्षीय पूजा 5000 मीटर और 10,000 मीटर स्पर्धाओं में भाग लेती हैं। उन्होंने 2024 में राजस्थान की तरफ से इंडियन ग्रां प्री दो में तीसरा स्थान हासिल किया था, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले साल 23 नवंबर को मुंबई में इंडियन ऑयल डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन जीतने के बाद उन्हें डोप टेस्ट के लिए चुना गया था।

भीड़ में भाग गई

मौखिक सूचना मिलने के बाद एथलीट को फिनिश लाइन से डोपिंग कंट्रोल स्टेशन (डीसीएस) तक ले जाने के लिए एक सहायक साथ में था। इसी दौरान एथलीट सहायक से अलग होकर भीड़ में भाग गई। पर्यवेक्षक ने एथलीट का पता लगाने की कोशिश की और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। उन्होंने इस संबंध में दौड़ के निदेशक को भी जानकारी दी। निदेशक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। पूजा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई इस वर्ष 3 फरवरी को शुरू की गई थी।

घुड़दौड़: द मिलेनियम फोर्स बेहतर

एजेंसी । मुंबई

गुरुवार शाम को महालक्ष्मी रेसकोर्स पर मुंबई घुड़दौड़ सत्र के 14वें दिन सात दौड़ों का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम की मुख्य दौड़ प्रथम श्रेंणी की आर एन कांगा ट्रॉफी है, जिसमें मात्र पांच प्रतिद्वंद्वी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदीप चौहान द्वारा प्रशिक्षित द मिलेनियम फोर्स की स्थिति बेहतर है और उसके जीत की संभावना है। पहली दौड़ शाम 4.30 बजे आरंभ होगी। विभिन्न दौड़ों के लिए हमारे चयन इस प्रकार हैः 1- द मिलेनियम फोर्स (प्र.), चागल (द्वि.), 2- घोस्ट ऑफ स्टोरी (प्र.), शादाय (द्वि.), 3- सिन्डरेला'स ड्रीम (प्र.), श्योरलिस्ट (द्वि.), 4- सोलेवा (प्र.), योरमॉययसबेबी (द्वि.), 5- एकितानिया (प्र.), विएननॉईज (द्वि.), 6- मिस मैजिक (प्र.), प्रेसियोसो (द्वि.), 7- मैटिस (प्र.), एमेजिंग रुल (द्वि.), दिन का सर्वोत्तमः घोस्ट ऑफ स्टोरी।

अभिषेक और वरुण आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

एजेंसी । मुंबई

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टी-20 रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। बुधवार को जारी नई रैंकिंग सूची के टी-20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा खराब फॉर्म के बावजूद बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं।

साल्ट दूसरे नंबर पर

बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, जबकि टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पाक ओपनर साहिबजादा फरहान दो पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा बल्लेबाज ईशान तीन पायदान की छलांग के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गए है जबकि भारत के शिवम दुबे दो पायदान ऊपर चढ़कर सातवें पर पहुंच गए हैं।

बुमराह सात पायदान चढ़े

स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महंगे प्रदर्शन के बावजूद गेंदबाजी में शीर्ष पर हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह सात पायदान चढ़कर आठवें नंबर पर आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन, वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती और इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने भी ताजा रैंकिंग में काफी तरक्की की है। जिम्बाब्वे के सिंकदर रजा ने शानदार प्रदर्शन से ऑलराउंडर्स रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 45 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 रन बनाए, जिससे वह ताजा सूची में पाक के सैम अयूब को पीछे छोड़कर शीर्ष ऑलराउंडर बन गए। अफगानिस्तान के अनुभवी मोहम्मद नबी तीन स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

बॉ ली वु ड

अरिजीत सिंह ने लिया यू-टर्न

प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की खबरों के बीच गायक अरिजीत सिंह ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। हालांकि, उनके बयान ने जहां कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट की है, वहीं आखिरी लाइन ने फैंस की उलझन और बढ़ा दी है। अरिजीत ने साफ किया कि फिलहाल वह नए गाने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देगी। उन्होंने बताया कि उनके कई अधूरे प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं, जो आने वाले समय में रिलीज होते रहेंगे। गायक के मुताबिक, उनके पास पहले से रिकॉर्ड किए गए और अधूरे गानों की लंबी सूची है। ये गाने इस साल और संभवतः अगले साल तक भी लगातार रिलीज होते रहेंगे। ऐसे में फैंस को उनकी आवाज सुनने का सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है।

फैंस के नाम भावुक संदेश

अरिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए अपने श्रोताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने लिखा कि यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो उन्हें सुनते हैं। उन्होंने अपने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए इस कठिन दुनिया में उनकी दयालुता की सराहना की। अपने फैसले को लेकर हो रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने प्रशंसकों से अपील की कि वे किसी भी तरह की बहस या सफाई देने में न पड़ें।

टेस्ट स्क्रीनिंग में 'रामायण' की जमकर तारीफ

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। फिल्म दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, हालांकि इससे पहले ही इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग कर ली गई है। खास बात यह है कि इस स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को दर्शकों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसे निर्माताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस खास टेस्ट स्क्रीनिंग का आयोजन लॉस एंजिल्स के सिनेमार्क प्लाया विस्टा में किया गया, जहां 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के चुनिंदा दर्शकों को फिल्म दिखाई गई। स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद दर्शकों ने फिल्म के भव्य पैमाने, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और भावनात्मक कहानी कहने के अंदाज की जमकर तारीफ की। शुरुआती प्रतिक्रियाओं के अनुसार फिल्म दर्शकों को एक भव्य सिनेमाई अनुभव देने में सफल रही है। फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जिनकी

परफॉर्मेंस को भी सराहा गया है। 'रामायण' को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है और अब सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बाद दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।

उर्वशी रौतेला ने काटा 16 करोड़ का डायमंड स्टड केक

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। 25 फरवरी को उन्होंने 32वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनका बर्थडे सेलिब्रेशन लग्जीरियस रहा। उन्होंने बर्थडे पर 7 टायर डायमंड स्टड केक कट किया। खबरें हैं कि ये केक 16 करोड़ रुपये का था। सोशल मीडिया पर उनके बर्थडे के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं। फैंस उनके केक और ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं। उर्वशी के इस केक ने बर्थडे को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है। बता दें कि उर्वशी अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहती हैं। पिछले साल उन्होंने 12 करोड़ की रॉल्स रॉयल खरीदी थी। हाल ही में उन्होंने ग्रीन मर्सिडीज जी वेगन खरीदी। इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही हैं। लग्जरी सेलिब्रेशन के साथ-साथ उर्वशी रौतेला ने अपना बर्थडे खास तरीके से भी मनाया। उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 गरीब लड़कियों की शादी में मदद की। इसमें उन्होंने उन परिवारों की मद की जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने सेरेमनी अडेंट की और उन दुल्हन से भी इंटरेक्ट किया और आशीर्वाद दिया।

रश्मिका -विजय रस्मों से करेंगे शादी

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का जश्न शुरू हो चुका है, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। इस खास मौके को कपल ने बेहद निजी रखा है, जिसमें केवल चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों की शादी दो अलग-अलग रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगी, जिससे उनकी सांस्कृतिक विविधता भी झलकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 फरवरी की सुबह रश्मिका और विजय तेलुगु हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह बंधन में बंधेंगे। इसके बाद शाम को कोडवा समुदाय की परंपराओं के अनुसार एक और समारोह आयोजित किया जाएगा, जो रश्मिका की जड़ों को समर्पित होगा। शादी से पहले एक खास रस्म में विजय की मां माधवी देवरकोंडा ने अपनी होने वाली बहू को परिवार की परंपरा के तहत खानदानी चूड़ियां भेंट कीं। गौरतलब है कि कपल ने 22 फरवरी को सोशल मीडिया के जरिए अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया था। शादी समारोह में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ करीबी चेहरे शामिल हो रहे हैं।

एनसीईआरटी किताब विवाद

न्यायपालिका से जुड़ी सामग्री हटाएगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद फैसला

एजेंसी | नई दिल्ली

एनसीईआरटी की कक्षा आठ की एक किताब में न्यायपालिका से जुड़ी विवादित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गंभीर आपत्ति जताई थी। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि एनसीईआरटी की कक्षा आठ की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित विवादास्पद अंशों को हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। परिषद ने पुस्तक को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी ने अध्याय से जुड़े विषय विशेषज्ञों और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक बैठक बुलाई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी ने इस मुद्दे पर फोन और संदेशों का जवाब नहीं दिया। परिषद के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

एनसीईआरटी विवाद पर क्या बोली सरकार?

सरकारी सूत्रों ने कहा कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन अध्याय जोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना ही था, तो इसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका - तीनों अंगों से संबंधित होना चाहिए था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बुधवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' के संदर्भों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस संस्था को 'बदनाम या अपमानित' करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में किसने उठाया मामला?

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तब आया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधित पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु पर चिंता व्यक्त की। सिब्बल ने कहा कि कानूनी बिरादरी के सदस्य इस बात से बहुत चिंतित थे कि स्कूली बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने इसे पूरी तरह से निंदनीय बताया। वरिष्ठ वकील ने शीर्ष अदालत को बताया, 'इस संस्था के सदस्य होने के नाते हमें यह जानकर गहरा दुख हुआ है कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। संस्था से हमारा गहरा संबंध है। हमारे पास पुस्तक की प्रतियां मौजूद हैं।'

सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी- एक दिन रुकिए

इसके जवाब में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह पहले से ही इस विवाद से अवगत थे और उन्हें न्यायपालिका के सदस्यों से इस मामले पर चिंता व्यक्त करने वाले कई पत्र प्राप्त हुए थे। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुस्तक की सामग्री से कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी परेशान थे। जब सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया, तो सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। सीजेआई ने टिप्पणी की, 'एक दिन रुकिए। यह निश्चित रूप से पूरी संस्था के लिए चिंता का विषय है। मैं धरती पर किसी को भी इस संस्था की गरिमा को धूमिल करने और इसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वह कितना भी ऊंचा पद पर हो, कानून अपना काम करेगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है।'

सीआरपीएफ ने आतंक पर नकेल के लिए बनाई नई रणनीति

3,000 से 6,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में 43 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित

एजेंसी | श्रीनगर

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत 3,000 से 6,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में 43 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह कदम अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, क्योंकि हाल के महीनों में आतंकवादी निचले इलाकों से हटकर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होने लगे हैं।

आतंकियों की मौजूदगी और पहलगाम हमला

खुफिया एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में लगभग 40 और कश्मीर घाटी में करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि दो स्थानीय आतंकियों की भी पहचान की गई है। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी, पहलगाम में तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई 2025 को कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान इन आतंकियों को मार गिराया था।

बेस पर तैनाती और विशेष उपकरण

सीआरपीएफ ने कश्मीर घाटी में 26 और जम्मू क्षेत्र में 17 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं, जिन पर आमतौर पर 15 से 20 जवान तैनात रहते हैं। ये टीमें ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकियों की तलाश और सर्च एवं असॉल्ट ऑपरेशन चलाती हैं। इन बेसों के लिए टैक्टिकल बूट, सर्दियों के जैकेट, स्लीपिंग बैग और सैटेलाइट फोन जैसे विशेष उपकरण खरीदे गए हैं। इसके साथ ही 3,300 से 8,900 फीट की ऊंचाई पर कुल 2,937 लंबी अवधि के ऑपरेशन चलाए गए हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

सीपीआई के सीनियर लीडर आर. नल्लाकन्नू का 101 की उम्र में निधन

चेन्नई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के सीनियर लीडर आर. नल्लाकन्नू का बुधवार को निधन हो गया। नल्लाकन्नू 101 साल के थे। वे पिछले 22 दिनों से चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार को उनकी हालत बिगड़ गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी। नल्लाकन्नू कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्रमिकों की भलाई और अधिकारों के लिए लगा दी। वे भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना करने वाले आखिरी जीवित नेता थे।

अज्ञात शरारती तत्वों ने नेहरू की प्रतिमा तोड़ी

सिल्चर। असम के कछार जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, जिससे राजनीतिक आक्रोश फैल गया। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने इस मामले को लेकर सरकार की चुप्पी को चिंताजनक बताया। गौरव गोगोई ने कहा कि इस कृत्य से उस स्वाधीनता सेनानी की विरासत का अपमान हुआ है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की रात बराक घाटी क्षेत्र के लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाइलापूल बाजार इलाके में हुई। पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उस खुदाई मशीन को जब्त किया है, जिससे प्रतिमा उखाड़ी गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई में नरमी बरतने का आरोप लगाया है।

BJP ने लॉन्च किया 'कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस' अभियान

नई दिल्ली। भाजपा ने 25 फरवरी को मेगा सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है, भाजपा के दिग्गज नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। पोस्ट में एआई फोटो से लेकर ग्राफिक्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है और कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। इस अभियान के चलते कई नेताओं ने अलग-अलग पोस्ट किए हैं, सबने #CompromisedCongress सीरीज टाइटल के साथ पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि "राहुल गांधी द्वारा भारत को वैश्विक मंच पर अपमानित करने के लिए बिना शर्ट पहने पुरुषों को एआई शिखर सम्मेलन में भेजना, भारत की छवि और हितों से समझौता करने की उनकी पारिवारिक विरासत की निरंतरता मात्र है"।

अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी याचिका खारिज

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पूरे घटनाक्रम की जानकारी शुरुआती जांच रिपोर्ट में शामिल करने की मांग की गई थी। यह याचिका IIT-दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले एक शख्स ने दायर की थी और इस याचिका में उसने कोर्ट से AAIB (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) की शुरुआती रिपोर्ट को पढ़ने और उसमें सुधार करते हुए इंजन के फ्लेम आउट यानी बंद होने का समय व फ्यूल स्विच के ट्रांजेक्शन (मैकेनिकल या मैनुअल) की जानकारी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

'न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं होती हैं'

याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने याचिकाकर्ता की मांग को पूरी तरह गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि तकनीकी जांच के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि यह PIL, जिसमें AAIB को ऐसी जानकारी सार्वजनिक रूप से बताने का निर्देश देने की मांग की गई है, बहुत गलत है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को जो जानकारी चाहिए उसके लिए उन्हें पहले सूचना के अधिकार (RTI) कानून का इस्तेमाल करना था। साथ ही बेंच ने कहा कि, 'हमारी सोची-समझी राय में ऐसी प्रार्थना मंजूर नहीं की जा सकती।

'पहले जाकर RTI से पता करने की कोशिश करिए'

सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी RTI के तहत देने योग्य होगी, वह दी जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील ने दोनों इंजनों के 'सर्ज' से फेल होने की आशंका जताई, लेकिन अदालत ने तकनीकी पहलुओं में जाने से इनकार करते हुए पिटीशन खारिज कर दी।

'जिस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए कहा, वह एक्सपर्ट ने तैयार की'

कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की चिंताओं को समझ सकता है, लेकिन उसके पास ऐसे मामलों पर फैसला करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'यह कानून का एक तय सिद्धांत है कि जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ काम करते हैं, उसे आमतौर पर एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देना चाहिए।

'अभी वह सिर्फ शुरुआती जांच रिपोर्ट है'

कोर्ट ने कहा कि जांच अभी जारी है और AAIB ने फिलहाल केवल शुरुआती रिपोर्ट दी है। पिछले साल 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो लंदन के गैटविक जा रही थी, सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकऑफ के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्टल परिसर में क्रैश हो गई थी।

इजरायल में आपका स्वागत है; तेल अवीव पहुंचे पीएम मोदी

एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने गले लगाकर किया वेलकम

एजेंसी | तेल अवीव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को तेल अवीव स्थित बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। यहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ उनका आत्मीय स्वागत किया और गले लगाकर अभिवादन किया। हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।

सोशल मीडिया पर दोस्ताना संदेश

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, "इजरायल में आपका स्वागत है, मेरे प्रिय मित्र नरेन्द्र मोदी।" यह प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे वर्ष 2017 में यहां आए थे।

द्विपक्षीय वार्ता और नेसेट को संबोधन

दो दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी की इजरायल के राष्ट्रपति आइज़ैक हर्जोग से भी शिष्टाचार भेंट निर्धारित है।

रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश

रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी यह यात्रा भारत और इजरायल के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने दोनों देशों के साझा विजन पर जोर देते हुए कहा कि इससे भविष्य और अधिक समृद्ध होगा।

रणनीतिक साझेदारी पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग तेज़ी से बढ़ा है। नेतन्याहू के साथ बातचीत में इन सभी क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए जाएंगे।

इजरायली मीडिया में ऐतिहासिक यात्रा

इजरायली मीडिया ने इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। समाचार पत्रों ने इसे "रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने वाली यात्रा" करार दिया है। यरुशलम सहित कई शहरों में इस दौरे को लेकर उत्साह देखा गया।

तिरंगे के रंग में सजी संसद

संसद भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर भारतीय और इजरायली झंडे लगाए गए हैं। नेसेट को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया है। तैयारियों में जुटे लोग भारतीयों का 'नमस्ते' कहकर अभिवादन करते नजर आए, जिससे पूरे शहर में मित्रता और उत्साह का माहौल दिखा।

सार्वजनिक हस्तियां किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बना सकतीं : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए भाईचारा अनिवार्य है। ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने 'घूसखोर पंडत' फिल्म से जुड़ी याचिका पर अपने 39 पृष्ठों के अलग फैसले में स्पष्ट किया कि भाषण, मीम, कार्टून या चित्रों के जरिए किसी समुदाय को बदनाम करना संविधान के खिलाफ है, और इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से उच्च पदों पर बैठे लोगों पर अधिक है।

फिल्म विवाद का निपटारा और नाम परिवर्तन

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति भुइयां की पीठ ने 19 फरवरी को फिल्म निर्माता नीरज पांडे के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। हलफनामे में नीरज पांडे ने बताया कि फिल्म का नाम बदल दिया गया है।

बंगाल में एसआईआर का काम निपटाएंगे झारखंड और ओडिशा के अधिकारी

एजेंसी | तेल अवीव

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बंगाल के SIR प्रोसेस में अब ओडिशा और झारखंड के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अफसरों को कम से कम तीन साल के काम का अनुभव होना चाहिए। दरअसल कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को SIR प्रोसेस में लगाने को कहा था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस काम में ढाई सौ अफसरों को लगाया गया है, लेकिन करीब 50 लाख फॉर्म पेंडिंग हैं।

तृणमूल कांग्रेस फैसले से खुश

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भी शामिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अब आधार कार्ड, हाईस्कूल का एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट भी मान्य दस्तावेज़ होंगे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में फंसी मंत्री वीना जॉर्ज हुईं घायल

एजेंसी | कोच्चि

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर घायल हो गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंत्री वीना जॉर्ज ट्रेन में चढ़ने के लिए कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, इसी दौरान यह घटना घटी। घटना के समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद राज्य विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमसीर ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री के हाथ और गर्दन में चोटें आई हैं। समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित दृश्यों में मंत्री, पुलिसकर्मियों के साथ, प्रदर्शनकारियों के बीच फंसी हुई दिखाई दीं।

अस्पताल में भर्ती की गईं वीना जॉर्ज

वीना जॉर्ज को कन्नूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता पी. जयराजन ने बताया कि उनका इलाज गहन चिकित्सा इकाई (इंटेंसिव केयर यूनिट) में चल रहा है। कुछ मरीजों से जुड़ी कथित चिकित्सा लापरवाही की घटनाओं के बाद पिछले एक सप्ताह से जॉर्ज को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

खबर पत्तर | 30 किलोवाट क्षमता के इन लेजर हथियारों का अभी परीक्षण चल रहा है

लंबी दूरी तक हमले में सक्षम लेजर हथियार बनाएगा डीआरडीओ

एजेंसी | नई दिल्ली

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) भविष्य की युद्ध चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लेजर हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। संगठन अत्याधुनिक पल्स लेजर तकनीक पर आधारित ऐसे हथियार तैयार कर रहा है, जो 300 किलोमीटर तक ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम होंगे। इससे दुश्मन के उपग्रहों को भी निशाना बनाना संभव हो सकेगा।

मौजूदा क्षमता और परीक्षण चरण

सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ पहले ही 3 किलोमीटर तक मार करने वाले लेजर हथियार विकसित कर चुका है। वर्तमान में 30 किलोवाट क्षमता वाले इन हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य इनकी रेंज और शक्ति को कई गुना बढ़ाकर लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयोगी बनाना है।

वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा

इस समय अमेरिका, चीन, रूस, इस्राइल और भारत ऐसे देश हैं, जो लेजर हथियार विकसित कर चुके हैं। इस्राइल के पास करीब 10 किलोमीटर तक मार करने वाले लेजर हथियार मौजूद हैं, जिनका हाल के समय में उपयोग भी किया गया है। हालांकि अब सभी देश लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों पर काम कर रहे हैं।